www.tamsasanket.com
वर्षः 05 || अंक 352 || लखनऊ
रविवार
29 मार्च 2026 || पृष्ठः 04 || मूल्यः ₹ 2
आज़ादी का अमृत महोत्सव
समूह संपादक- डॉ. ओ.पी. मिश्रा
दैनिक
तमसा संकेत
https://epaper.tamsasanket.com
लखनऊ व अम्बेडकर नगर से एक साथ प्रकाशित
डॉ. लोहिया की जन्म भूमि से सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र

मौसम
सूर्योदय: 06:02
सूर्यास्त: 06:21
अधिकतम: 35°00
न्यूनतम: 23°00

पेज 03

विशेष समाचार — चिकित्सा मित्रों के बारे में भी विचार... >> पेज 02
डंपिंग यार्डों से कूड़ा उठान में देरी... >>पेज 04
2 हफ्ते आईपीएल से बाहर रह सकते हैं...

फास्ट न्यूज

राजस्थान में बीजेपी को 87, कांग्रेस को 25 करोड़ डोनेशन

जयपुर । राजस्थान में साल 2024-25 में राजनीतिक पार्टियों को कुल 112.97 करोड़ का चंदा मिला है। चुनाव आयोग में राजनीतिक पार्टियों की तरफ से दिए गए चंदे के ब्यौरे पर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है।

जांच आरोप

रेप आरोपी बाबा के खिलाफ 100 शिकायतें मिलीं

नासिक (महाराष्ट्र) । महाराष्ट्र के नासिक में गिरफ्तार स्वयंभू 'बाबा' अशोक खरात के खिलाफ दो और मामले दर्ज हुए हैं। पुलिस ने शनिवार को बताया कि जांच कर रही SIT को पिछले पांच दिनों में फोन पर 100 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं। SIT ने लोगों से जानकारी लेने के लिए दो फोन नंबर जारी किए हैं। खरात के खिलाफ कुल 10 FIR दर्ज हो चुकी हैं। इनमें से 8 मामले यौन शोषण और 2 मामले धोखाधड़ी के हैं। खरात को 18 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। महिला ने आरोप लगाया था कि खरात ने तीन साल तक उसका बार-बार रेप किया।

इंडिगो फ्लाइट का इंजन फेल

नई दिल्ली । विशाखापट्टनम से दिल्ली आ रही इंडिगो की फ्लाइट 6E 579 की शनिवार सुबह दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंजन बंद होने की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट में 160 यात्री सवार थे। विमान की सुरक्षित लैंडिंग के लिए एयरपोर्ट के रनवे 28 पर 'फुल इमरजेंसी' लागू की गई थी। रनवे के चारों ओर दमकल की गाड़ियां और एंबुलेंस मौजूद थीं, जिस बोइंग 737 विमान के इंजन में खराबी आई, वह तुर्की की कोरेनडन एयरलाइन्स से लीज पर लिया गया है।

होर्मुज स्ट्रेट और व्यापार पर चर्चा की, ईरान जंग पर बात करने पाकिस्तान जाएंगे 3 देश

पीएम मोदी ने सऊदी क्राउन प्रिंस से बात की

चर्चा

तमसा संकेत, एजेंसी

तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन डीसी । अमेरिका-इजराइल और ईरान जंग का 29वां दिन है। पीएम मोदी ने शनिवार को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर ईरान जंग को लेकर बात की।

दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि होर्मुज स्ट्रेट जैसे समुद्री रास्ते खुले और सुरक्षित रहने चाहिए और अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रभावित नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी ने ऊर्जा ठिकानों पर हो रहे हमलों की निंदा की। वहीं, ईरान

जंग के बीच तुर्किये, मिस्र और सऊदी अरब के विदेश मंत्री 30 मार्च को पाकिस्तान पहुंचेंगे। यहां वे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान के ईरान और सऊदी अरब दोनों से बेहतर रिश्ते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसलिए पाकिस्तान को विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए बेहतर जगह माना जा रहा है। >> (शेष पेज 04 पर)

इस्लामाबाद में होने वाली इस बैठक में मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा होगी। युद्ध शुरू होने के बाद यह पहली बड़ी बैठक मानी जा रही है, जिसमें कई देशों के विदेश मंत्री एक साथ शामिल होंगे।

TEHRAN TIMES
Welcome to Hell
US troops who step foot on Iranian soil will leave only in a coffin

ईरानी अखबार की अमेरिका को चेतावनी, लिखा- नरक में स्वागत है

ईरान से छपने वाले अंग्रेजी अखबार तेहरान टाइम्स ने अपने पहले पन्ने पर अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है। अखबार ने 'नरक में स्वागत है' (वेलकम टू हेल) लिखते हुए कहा है कि अगर अमेरिकी सैनिक ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए आए तो वे सिर्फ ताबूत में ही वापस जाएंगे। यह बयान उस समय आया है जब खबरें चल रही हैं कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में करीब 10,000 और सैनिक भेजने पर विचार कर रहा है। >> (शेष पेज 04 पर)

अडाणी डिफेंस ने आर्मी को सौंपी 2,000 मशीन गन

ग्वालियर । मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अडाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस ने भारतीय सेना को 2,000 'प्रहार' लाइट मशीन गन की पहली खेप सौंपी। यह 7.62 मिमी कैलिबर के हथियार ग्वालियर के स्मॉल आर्म्स कॉम्प्लेक्स में बनाए गए हैं। सरकार इन हथियारों का इस्तेमाल LAC और LoC पर सुरक्षा और मारक क्षमता बढ़ाने के लिए करेगी। 'प्रहार' LMG की मारक क्षमता 1,000 मीटर तक है, जिससे दुश्मनों को दूर से निशाना बनाया जा सकता है। मशीन गन 8 किलोग्राम की हैं, जिनकी लंबाई 1100 mm है। शनिवार को ग्वालियर स्थित प्लांट में सेना को LMG सौंपने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें रक्षा मंत्रालय के डीजी ए. अंबरासु, कंपनी के CEO आशीष राजवंशी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। अधिकारियों ने मशीन गन की पहली खेप लेकर जा रहे ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

ईरान की जंग में पहली बार हूती ने इजरायल पर दागी मिसाइल

अरब मुल्कों में खतरा बढ़ा जंग फैलती नजर आ रही

दावा

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली । अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग अब और ज्यादा फैलती नजर आ रही है. इजरायली सेना ने दावा किया है कि यमन से इजरायल की तरफ एक मिसाइल दागी गई है. यह पहली बार है जब इस जंग के दौरान यमन से सीधे हमले की बात सामने आई है. इस दावे ने पूरे मिडिल ईस्ट में बड़े क्षेत्रीय युद्ध की आशंकाओं को और तेज कर दिया है. इस हमले से कुछ घंटे पहले ही हूती ने संकेत दिए थे कि अगर ईरान के खिलाफ कार्रवाई तेज होती है तो वे भी हस्तक्षेप कर सकते हैं. हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इजरायल का दावा

इजरायल ने यमन से मिसाइल दागे जाने का दावा किया है. हालांकि, हूती की तरफ से इस दावे पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई

इस बात की ओर इशारा करता है कि हूती अब इस संघर्ष में सक्रिय रूप से शामिल हो सकता है।

>> (शेष पेज 04 पर)

अयोध्या में मंत्री दयाशंकर के यज्ञ स्थल में लगी आग

राममंदिर से 800 मीटर दूर हादसा

घटना

तमसा संकेत, एजेंसी

अयोध्या । अयोध्या में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के यज्ञ स्थल में शनिवार दोपहर 12 बजे अचानक भीषण आग लग गई। एक एकड़ में फैला यज्ञ स्थल कुछ ही मिनटों में जलकर खाक हो गया। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त यज्ञशाला खाली थी। करीब डेढ़ घंटे पहले ही मंत्री का 9 दिवसीय लक्ष्मीनारायण महायज्ञ पूर्ण हुआ था। उस वक्त करीब 50 हजार से अधिक लोग मौजूद थे। यज्ञ स्थल, राम मंदिर से 800 मीटर दूर है। बताया जा रहा है कि यज्ञ के पूर्ण होने के बाद एक नारियल फूटने से चिंगारी निकली, जिससे कपड़े से

यज्ञशाला खाली नहीं होती तो बड़ा हादसा हो जाता

बने पंडाल में आग लग गई। परिवहन मंत्री ने कहा फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद था। उसने तुरंत आग पर काबू पा लिया। कोई जनहानि नहीं हुई है। सब नियंत्रित है। यज्ञ में शामिल एक व्यक्ति ने बताया- मंत्री के 9 दिवसीय महायज्ञ के लिए यज्ञशाला में 1,251 हवन कुंड बने थे।

>> (शेष पेज 04 पर)

अमित शाह का गुवाहाटी में रोड शो : अमित शाह बोले ममता चुनाव में विक्टिम कार्ड खेलती हैं

असम में 90 से ज्यादा सीटों से बनाएंगे सरकार : शाह

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली/ तिरुवनंतपुरम/ गुवाहाटी/ कोलकाता/ चेन्नई । गृहमंत्री अमित शाह ने शनिवार को गुवाहाटी (असम) में रोड शो किया। इसके पहले शाह ने कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ आरोप पत्र (चार्जशीट) जारी किया। शाह ने कहा, 'इसमें TMC सरकार के 15 साल के काले कारनामों का जिक्र है, ये जनता की चार्जशीट है। बंगाल में अराजकता और बदहाली है। यहां की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है।' मार्च 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले

ममता के सिर में चोट में लगी थी, जबकि 2021 में विधानसभा चुनाव के पहले उनके पैर में चोट लगी थी। उधर, TMC ने भी भाजपा के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। केरल के मंत्री और एलडीएफ के उम्मीदवार वी शिवनकुट्टी ने शनिवार को कहा कि वे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव

भाजपा की मुहर लगे चुनाव दस्तावेज मामले में एक्शन

केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रतन यू केलकर ने शनिवार को उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी और एक अनुभाग अधिकारी को उनके मूल विभागों में वापस भेज दिया। यह कार्रवाई भाजपा की मुहर लगे एक चुनाव आयोग के दस्तावेज को लेकर की गई, जिसे राजनीतिक दलों को भेजा गया था।

चंद्रशेखर से उनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास पर खुली बहस के लिए तैयार हैं। >> (शेष पेज 04 पर)

राहुल ने सुधाकरन से मुलाकात की

राहुल गांधी ने शनिवार को नई दिल्ली में कन्नूर लोकसभा सांसद के सुधाकरन से मुलाकात की। इस मुलाकात में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। >> (शेष पेज 04 पर)

'ममता दीदी ने हमेशा विक्टिम कार्ड की राजनीति की है। कभी पैर तुड़वा लेती हैं, कभी सिर पर पट्टी बंधवा लेती हैं, कभी बीमार हो जाती हैं और कभी चुनाव आयोग को गालियां देती हैं। लेकिन बंगाल के लोग अब ममता दीदी की विक्टिम कार्ड पॉलिटिक्स को अच्छी तरह समझ गए हैं।'

\- अमित शाह

'नया उत्तर प्रदेश' आज प्रगति की एक नई उड़ान भरते हुए उद्घोष कर रहा : योगी

जेवर एयरपोर्ट बनकर तैयार

मोदी ने देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, नोएडा में बोले- युद्ध के संकट से देश को एकजुट होकर लड़ना है

- पश्चिमी एशिया में युद्ध से उपजे संकट का पूरी ताकत से सामना कर रहे
- विकसित यूपी की उड़ान का प्रतीक बनेगा एयरपोर्ट
- विकसित यूपी-विकसित भारत अभियान का नया अध्याय शुरू - पीएम मोदी

उद्घाटन

तमसा संकेत, एजेंसी

नोएडा । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को यूपी के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज-1 का उद्घाटन किया। यह अभी देश का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। 4 फेज पूरे होने पर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा। पीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से इजराइल-अमेरिका और ईरान की जंग से उपजे संकट से एकजुट होकर लड़ने की अपील की। उन्होंने कहा- कल सभी राज्यों के सीएम से चर्चा हुई। >> (शेष पेज 04 पर)

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 52 स्क्वायर किमी में बनना प्रस्तावित है। पूरा बनने की डेडलाइन 2040 है।

पीएम मोदी की लोगों से अपील- वैश्विक संकट का मिलकर सामना करें

पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए सबका प्रयास बहुत जरूरी है। ये आवश्यक है कि 140 करोड़ देशवासी कड़े से कड़ा परिश्रम करें और वैश्विक संकट का मिलकर सामना करें। युद्ध हो रहा है। इसका सामना कैसे करें ये संसद में बताया है। देश के सभी सीएम से हमारी चर्चा हुई है।

देशवासियों से कहूंगा कि शांत मन से धैर्य के साथ एकजुटता के साथ मिलजुलकर इस संकट का सामना करना है। ये विश्व को परेशान करने वाला संकट है। हमें अपने देश की सबसे ज्यादा चिंता करनी है। यही हम भारतीयों की सबसे बड़ी ताकत है।

हमारी सरकार की प्राथमिकता देश के नागरिकों की सुविधा

पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में एयरपोर्ट पर मेंटेनेंस की सुविधा नहीं है। 85 प्रतिशत हवाई जहाजों को मेंटेनेंस और मरम्मत के लिए विदेश भेजना पड़ता है। हमारी सरकार ने ठाना है कि इस क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। बड़े पैमाने पर एमआरओ सुविधा बढ़ाई जा रही है। जेवर पर भी ये सुविधा शुरू की जा रही है।

इससे देश की कमाई बढ़ेगी। युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता देश के नागरिकों की सुविधा है। देश के नागरिकों का समय बचे और जेब पर ज्यादा बोझ भी न पड़े, ये हमारा लक्ष्य है।

दिल्ली-मेरठ नमो भारत ट्रेन का बड़ा फायदा हो रहा है। अब तक ढाई करोड़ लोग सफर कर चुके हैं। पहले घंटों का समय लग जाता था, अब वो सफर मिनटों में पूरा हो रहा है।

मोदी बोले-यूपी के पुराने सीएम नोएडा आने से डरते थे, मुझे भी डराने की कोशिश हुई, कहा था- अभी-अभी पीएम बने हैं, मत आइए

पीएम मोदी विपक्ष के लिए बोले- ऐसी बातें करने से बचें, जो देश के लिए नुकसानदायक

पीएम मोदी ने कहा कि देश के सभी राजनीतिक दलों से आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के संकट में ऐसी बातें करने से बचें, जो देश के लिए नुकसानदायक हैं। उन्होंने कहा कि जो भारतीयों के हक में है, हित में है, वहीं भारत सरकार की नीति और रणनीति है। >> (शेष पेज 04 पर)

> पश्चिम एशिया में युद्ध चल रहा है। इसके चलते कई देशों में संकट पैदा हो गया है। भारत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस युद्ध-प्रभावित क्षेत्रों से मंगाता है। इसलिए सरकार हर वह कदम उठा रही है, जिससे सामान्य परिवारों और किसानों पर बोझ न पड़े। 140 करोड़ देशवासी इस मुसीबत का एकजुट होकर सामना करें - पीएम मोदी

एयरपोर्ट 2040 तक पूरा बनकर तैयार होगा

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 52 स्क्वायर किमी में बनना प्रस्तावित है। पूरा बनने की डेडलाइन 2040 है। नोएडा एयरपोर्ट अथॉरिटी से जुड़े अफसरों ने बताया- एयरपोर्ट से फ्लाइट मई से शुरू हो सकती है। एयरपोर्ट की सबसे बड़ी खूबी यह है कि एंट्री के बाद 20 मिनट से कम समय में बोर्डिंग संभव है। एशिया की सबसे बड़े एयरपोर्ट की बात करें तो अभी चीन का बीजिंग डेक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसका एरिया 47 स्क्वायर किमी है। नोएडा को पहले अंधविश्वास के कारण अपने हाल पर छोड़ दिया गया था।

>> (शेष पेज 04 पर)

2014 से पहले देश में 74 एयरपोर्ट थे, आज 160 हैं : मोदी

पीएम मोदी ने कहा- किसी भी देश में एयरपोर्ट सिर्फ एक संचालन की सुविधा नहीं होती। ये एयरपोर्ट प्रगति को उड़ान देते हैं। 74 एयरपोर्ट 2014 से पहले देश में थे। आज 160 एयरपोर्ट हैं। आज महानगरों के साथ छोटे शहरों में हवाई कनेक्टिविटी पहुंच रही है। पहले की सरकार मानती थी कि हवाई यात्रा अमीरों के लिए ही होनी चाहिए। लेकिन, भाजपा की सरकार ने सामान्य लोगों के लिए हवाई यात्रा को आसान बना दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी में तेजी से हवाई एयरपोर्ट की संख्या 17 कर दी है। भाजपा सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि एयरपोर्ट भी रहे और किराया-भाड़ा भी सामान्य परिवारों की पहुंच में रहे।

यह विश्वस्तरीय एयरपोर्ट न केवल उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई तक ले जाने का आधार बनेगा बल्कि निवेश, व्यापार और औद्योगिक विकास को गति देते हुए लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगा।

\- सीएम योगी

गोवा सेक्स स्कैंडल में 100 से भी ज्यादा नाबालिग पीड़ित : कांग्रेस

पणजी । गोवा में नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार भाजपा पार्षद के बेटे को लेकर कांग्रेस ने नए दावे किए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकर ने आरोप लगाया कि इस सेक्स स्कैंडल में 100 से ज्यादा नाबालिग लड़िकयां पीड़ित हैं। साउथ गोवा के कर्चोरेम म्युनिसिपल काउंसिल के सदस्य सुशांत नाइक के 20 साल के बेटे सोहम पर नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाने और उन्हें फैलाने का आरोप है। पुलिस ने अब तक सोहम के खिलाफ तीन शिकायतों की पुष्टि की है। सोहम के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, गोवा चिल्ड्रन एक्ट, भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट के तहत चार मामले दर्ज किए गए हैं। गोवा प्रदेश महिला कांग्रेस के प्रोटेस्ट मार्च के दौरान अमित पाटकर ने कहा कि यह मामला जितना सामने आया है, उससे कहीं बड़ा हो सकता है। उनका दावा है कि आरोपी पिछले तीन सालों से इस तरह की गतिविधियों में शामिल था और पीड़ित कर्चोरेम, मडगांव, वास्को और पोंडा जैसे इलाकों से हैं।

बेंगलुरु में प्रोफेसर ने स्टूडेंट को आतंकी कहा, सस्पेंड

बेंगलुरु। कर्नाटक के बेंगलुरु में निजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के खिलाफ स्टूडेंट को आतंकी कहने पर शनिवार को केस दर्ज हुआ। यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया है। घटना का 58 सेकेंड का वीडियो वायरल है।

न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, पुलिस ने मामले पर खुद से नोटिस लिया। घटना 24 मार्च की है।

एफआईआर के मुताबिक, विशेष समुदाय के छात्र ने प्रोफेसर से क्लास से बाहर जाने की परमिशन मांगी। इस पर प्रोफेसर को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा- शर्म नहीं आती तुमको आतंकी।

प्रोफेसर यहां नहीं रुके, उन्होंने कहा, 'मैंने सोचा था कि मैं आज बहुत शांत रहूंगा। ईरान युद्ध तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से हुआ। ट्रम्प तुम्हें ले जाएगा। तुम बेवकूफ होतुम नरक में जाओगे।'

सम्पादकीय

खतरे में ट्रंप की साख, युद्ध से निकलने का खोज रहे मौका

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के बिजली और ऊर्जा ठिकानों को तबाह करने की धमकी देने के बाद पहले जिस तरह पांच दिन तक इन ठिकानों पर हमले टालने की घोषणा की और अब कहा कि कुछ और दिन की मोहलत दे रहे हैं, उससे यही लगता है कि वे समझौते के मूड में आ गए हैं। हालांकि रह-रहकर वे ईरान को धमकाते भी हैं, पर उन्होंने जिस तरह होर्मुज समुद्री मार्ग खोलने के लिए भी समयसीमा बढ़ा दी, उससे यही लगता है कि वे किसी तरह इस युद्ध से निकलना चाह रहे हैं। उनके ऐसे संकेतों के बाद भी यह कहना कठिन है कि अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच छिड़ा युद्ध थम जाएगा। इसका कारण यह है कि ईरान बिना इस भरोसे अपने कदम पीछे खींचने के लिए तैयार नहीं कि उस पर फिर हमला नहीं किया जाएगा। जिस तरह ईरान अमेरिका की युद्ध विराम संबंधी शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं हो सकता, वैसे ही अमेरिका और इजरायल के लिए भी उसकी शर्तें मानना संभव नहीं। वास्तव में इसी कारण युद्ध थमता नहीं दिख रहा है। जहां इजरायल ईरान को निशाना बनाने में लगा हुआ है, वहीं ईरान उस पर हमले करने के साथ ही अपने पड़ोसी देशों पर मिसाइलें दाग रहा है। यह स्वाभाविक ही है कि इससे इन देशों का धैर्य जवाब दे रहा है। ये देश इसलिए अधिक परेशान हैं कि ईरान उनके नागरिक और ऊर्जा ठिकानों को भी निशाना बना रहा है।

यदि खाड़ी के देशों ने ईरान पर जवाबी हमले करने शुरू किए तो युद्ध एक नए मोड़ पर पहुंच जाएगा। निःसंदेह ऐसा न तो ट्रंप चाहेंगे और न ही विश्व के अन्य देश, क्योंकि ऊर्जा संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी चपेट में भारत समेत अन्य एशियाई देश ही नहीं, यूरोप और अमेरिका भी आ गए हैं।

इस ऊर्जा संकट के लिए प्रत्यक्ष रूप से तो ईरान जिम्मेदार है, जिसने होर्मुज जल मार्ग बाधित कर रखा है, पर परोक्ष जिम्मेदार अमेरिका ही है, जिसने बिना कुछ सोचे-समझे इजरायल के साथ मिलकर ईरान पर हमला बोल दिया। ईरान ने अपनी जवाबी कार्रवाई से न केवल अमेरिका-इजरायल को तंग किया है, बल्कि पड़ोसी देशों को भी। यदि ईरान और अधिक समय तक जवाबी कार्रवाई करने में समर्थ बना रहता है तो अमेरिकी राष्ट्रपति को अपना रुख और नरम करने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है। इस स्थिति में उनका प्रभाव कम ही होगा-न केवल अमेरिका में, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी। ध्यान रहे कि विश्वव्यापी ऊर्जा संकट के लिए वही जिम्मेदार माने जा रहे हैं और घरेलू स्तर पर भी उनका विरोध बढ़ रहा है। ईरान युद्ध के पहले उन्होंने जिस तरह वेनेजुएला पर हमला किया और अपनी मनमानी टैरिफ नीति से अपने मित्र देशों समेत दुनिया भर को तंग किया, उसके चलते उनकी विश्वसनीयता और साख पहले ही कम हो चुकी है।

डॉ. ओ.पी. मिश्र

चिकित्सा मित्रों के बारे में भी विचार करना होगा

66

स्वास्थ्य मंत्री ने बातचीत के दौरान यह स्वीकार किया कि देश में मानक के अनुरूप डॉक्टरों की कमी जरूर है लेकिन सरकार यह प्रयास जरुर कर रही है कि हर व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा निशुल्क और उसके घर के नजदीक मिले।

हम सब लोग यह बात भली बात जानते हैं कि आज भी अपने देश भारत की 70% आबादी गांवो में रहती है। इसी के साथ यह भी हकीकत है कि 70 फिसदी क्वालिफाइड डॉक्टर अपने अनुभव और ज्ञान की मशाल जलाकर लोगों की जिंदगी में रोशनी करने के लिए गांव में जाना नहीं चाहते।

तो फिर यह सवाल उठना लाजिमी है कि गांव में रहने वाले असली भारत के निवासियों का इलाज कौन करेगा ?

क्योंकि सरकारी डॉक्टर तो गांव जाएंगे नहीं और अगर जाएंगे भी तो रजिस्टर पर। हकीकत में नहीं उनकी जगह कोई अन्य व्यक्ति जाएगा जिसका सरकारी डॉक्टर अपने वेतन का 10-15% देते हैं सरकार या स्वास्थ्य विभाग भले ही यह बात स्वीकार न करें लेकिन हकीकत यही है कि सरकारी डॉक्टर शहर में रहकर अपनी निजी प्रैक्टिस करते हैं और उनके स्थान पर कोई कथित चिकित्सक 15 से 20 हजार रुपये महीने लेकर उनका काम करता है। यह कथित चिकित्सक कोई और नहीं बल्कि चिकित्सा मित्र होता है जो अपने अनुभव के आधार पर ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराता है। यह वहीं चिकित्सा मित्र है जिसे मीडिया के लोग झोलाछाप डॉक्टर कहती है। यह वहीं चिकित्सा मित्र हैं जिन्हें शहर में रहने वाले बड़े साहब के गांव में रहने वाले माता-पिता अपना इलाज करवाते हैं। यह वहीं चिकित्सा का मित्र है जिन्होंने कोरोना कल में अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों को बहुत सस्ते में इलाज किया था और मृत्यु दर एक प्रतिशत से भी काम रही थी। यह वही चिकित्सा मित्र है जिनकी आफ द रिकॉर्ड जिला प्रशासन ने भी तारीफ की थी । यह वही चिकित्सा मित्र है जो तंबाकू मुक्त भारत अभियान प्रतिवर्ष चलते हैं। यह वहीं चिकित्सा मित्र हैं जो सरकार की स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचने में अहम भूमिका निभाते हैं । इसके बावजूद इन्हें झोलाछाप डॉक्टर कहा जाता है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन तथा सीएमओ के द्वारा इनको परेशान किया जाता है प्रताड़ित किया जाता है वसूली की जाती है तथा जेल भेजा जाता है और क्लिनिक सील की जाती है । एक सर्वे के अनुसार इस तरह के अनुभव प्राप्त कथित चिकित्सकों की संख्या पूरे देश में करीब 50 लाख है जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश में 18 से 20 लाख के बीच है। अनुभव के आधार पर प्राथमिक उपचार करने वाले तथा आकस्मिक चिकित्सा सुविधा प्रदान करने वाले यह चिकित्सक पिछले करीब 30 वर्षों से अलग-अलग संगठनों के द्वारा अपनी समस्याएं तथा अपनी बातें राज्य सरकारों तक पहुंचा रहे हैं। इसके बावजूद सरकार के कानों पर जू नहीं रेग रही है ।

इसी बीच पता चला है कि बिहार सरकार तथा आंध्र प्रदेश सरकार ने इन बातों का संज्ञान लिया है लेकिन राज्य सरकार कभी गेंद सरकार के पाले में फेंकती है तो कभी केंद्र सरकार कहती है कि यह राज्य सरकारों का जूरिडिक्शन है। इन्हीं तमाम समस्याओं तथा बातों को ध्यान में रखकर 2 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित आंध्र प्रदेश भवन में लगभग 15 राज्यों के उन प्रमुखों को बुलाया गया था जो अपने-अपने राज्यों में कथित झोलाछाप डॉक्टरों को एक समय बद्ध प्रशिक्षण प्रदान कर चिकित्सा मित्र बनाने तथा उन्हें प्राथमिक उपचार का अधिकार प्रदान करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसमें उत्तर प्रदेश में कार्यरत एक मात्र संगठन इंडियन रूरल मेडिकोज सोसायटी भी शामिल था। बैठक के बाद राष्ट्रीय स्तर पर एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी का गठन पूर्व विधान परिषद सदस्य टीडी जनार्दन के नेतृत्व में किया गया । कमेटी का नाम रखा गया ऑल इंडिया बेसिक हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन तथा इसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर के जी गोविंदा रेड्डी।

इस संगठन के आंध्र प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब , गुजरात , मध्य प्रदेश , राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटक के प्रतिनिधि को शामिल किया गया। संगठन की लीगल एडवाइजर के रूप में डॉक्टर एल एन राव तथा को अध्यक्ष के रूप में मुकेश अग्रवाल का चयन हुआ। संगठन के गठन के बाद पिछली 25 मार्च को संगठन के 12 सदस्यीय सिस्ट शिस्टमंडल जिसमें सर्वश्री अंशु तिवारी (बिहार) डॉक्टर ओपी मिश्रा तथा योगेश जायसवाल (उत्तर प्रदेश) धनपाल गोयल (पंजाब) सी एस राव (गुजरात) बी पी राजू (आंध्र प्रदेश) पी मोहन (तेलंगाना) जी एस प्रसाद (आंध्र प्रदेश) के साथ ही बाला श्रीनिवास राव तथा एम0 सुधाकर प्रमुख थे। ने भारत सरकार के नागरिक उड्यन मंत्री श्री किंजारपू राममोहन नायडू जी के नेतृत्व में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा से उनके संसद भवन स्थित कक्ष में मिलकर उन्हें एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में मांग की गई कि अनुभव के आधार पर कम से कम 10 वर्ष से चिकित्सा कार्य कर रहे चिकित्सकों को पंजीकृत करके प्राथमिक उपचार करने का अधिकार प्रदान किया जाए।

स्वास्थ्य मंत्री श्री नड्डा ने चार पृष्ठ के ज्ञापन को पूरे मनोयोग से पढ़ा और स्वीकार किया कि अमेरिका जैसे विकसित देश में भी इस तरह के हेल्थ प्रोवाइड्स की व्यवस्था है। इस बात का सबूत संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर के जी गोविंदा रेड्डी ने अपने तर्कों में दिया जिसकी पुष्टि केंद्रीय नागरिक उड्यन मंत्री श्री राम मोहन नायडू जी ने की। यह सब सुनने समझने तथा पढ़ने के बाद स्वास्थ्य मंत्री श्री नड्डा जी ने अपने विशेष सहायक को बुलाकर इस पर एक्सरसाइज करने का निर्देश दिया ताकि अनुभव के आधार पर चिकित्सा कार्य करने वाले लाखों लोगों को भी समाज की मुख्य धारा में समाहित किया जा सके। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के संगठन प्रमुखों से भी कहा है कि आप अपने राज्य का स्टेटस तथा अपने सदस्यों का डेटा भी हमको उपलब्ध कराए।

भारतीयों से भयभीत अमेरिकी, रोकना अमेरिका के लिए भी हानिकारक

हाल में प्यू रिसर्च से जुड़ी खबर में बताया गया कि अमेरिका में रहने वाले तमाम धार्मिक समूहों में हिंदू सबसे अधिक पढ़े-लिखे हैं। इसके बाद यहूदी समुदाय है। 70 प्रतिशत हिंदुओ ने स्नातक या उससे अधिक पढ़ाई की है। इसी क्रम में 65 प्रतिशत यहूदियों के पास स्नातक या उससे अधिक पढ़ाई की योग्यता है। इन दोनों समूहों की तुलना में अमेरिकियों में मात्र 35 प्रतिशत लोगों के पास इतनी शिक्षा है।

मुस्लिम, बौद्ध और ईसाई समूहों में दस में से चार के पास स्नातक तक की शिक्षा है। प्रोटेस्टेंट ईसाइयों के पास भी औसत से अधिक शिक्षा है, जबकि कैथोलिक समूहों की शिक्षा राष्ट्रीय औसत से कम है। प्यू रिसर्च से जुड़ी खबर यह भी बताती है कि अधिकांश भारतीय जो अमेरिका आए हैं, वे उच्च शिक्षा लेकर ही आए हैं।

एक अन्य खबर में बताया गया कि भारतीयों को भारत से बहुत कम शिकायत है। वे अपने देश के निंदा अभियानों में शामिल नहीं होते। सिर्फ तीन प्रतिशत भारतीय ही अपने देश के बारे में नकारात्मक राय रखते हैं। अमेरिका में अपने देश को नापसंद करने वाले लोगों की संख्या 20 प्रतिशत और ब्रिटेन में 29 प्रतिशत है। भारत, स्पेन, कनाडा, इंडोनेशिया आदि देशों के लोगों को इस पर भी गर्व है कि उनके देश में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। यह निष्कर्ष 25 देशों के 30 हजार लोगों से बातचीत करके निकाला गया।

अपने ही देश भारत की निंदा करने वाले तीन प्रतिशत लोगों में बुद्धिजीवी तबका और विशेष तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा प्रतीत होती है। इसका एक उदाहरण इस लेखिका को हाल की अमेरिका यात्रा के दौरान मिला। एक बड़े विश्वविद्यालय में भारत के बारे में एक संगोष्ठी थी। वहां जाना हुआ। बोलने वाले विश्वविद्यालय के वरिष्ठ भारतीय प्रोफेसर ही थे। लगभग दो घंटे के संबोधन और पीपीटी में उन्होंने जो चीजें दिखाईं, उनमें बारंबार यही कहा गया कि इस देश में यह बुराई है, वह बुराई है। यहां तो कुछ हुआ ही नहीं है।

क्षमा शर्मा

दो दिवसीय इस समागम ...

डॉ. शैलेश शुक्ला

इंदौर में 30 -31 मार्च को साहित्यिक पत्रिकाओं का राष्ट्रीय समागम

मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा आगामी 30 और 31 मार्च को इंदौर में आयोजित किया जा रहा दो दिवसीय 'साहित्यिक पत्रिका समागम' देशभर की साहित्यिक पत्रकारिता से जुड़े संपादकों, लेखकों, शोधार्थियों और प्रकाशन विशेषज्ञों को एक साझा मंच पर लाने वाला महत्वपूर्ण आयोजन माना जा रहा है। हिंदी सहित भारतीय भाषाओं की साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं के समक्ष बदलते समय में उत्पन्न हो रही चुनौतियों, उनके स्वरूप, सामग्री और भविष्य की दिशा पर गंभीर विमर्श के उद्देश्य से आयोजित यह समागम साहित्यिक जगत में विशेष उत्सुकता का केंद्र बना हुआ है। अकादमी के अनुसार, इस आयोजन के माध्यम से साहित्यिक पत्रकारिता के समक्ष उपस्थित आर्थिक, तकनीकी और पाठकीय संकटों पर न केवल चर्चा होगी, बल्कि उनके व्यावहारिक समाधान भी खोजने का प्रयास किया जाएगा। समागम का उद्घाटन 30 मार्च को प्रातः 11 बजे से होगा, जिसमें 'देश और समाज के प्रति साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं का दायित्व बोध : वीणा का शताब्दी संदर्भ' विषय पर विशेष विमर्श आयोजित किया जाएगा। इस सत्र में विभिन्न विश्वविद्यालयों और साहित्यिक संस्थाओं से जुड़े विद्वान तथा प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका 'वीणा' के संपादक अपने विचार व्यक्त करेंगे। उद्घाटन सत्र में साहित्यिक पत्रिकाओं की ऐतिहासिक भूमिका, सामाजिक चेतना के निर्माण में उनका योगदान तथा बदलते मीडिया परिवेश में उनकी जिम्मेदारियों पर विशेष चर्चा अपेक्षित है। इसके बाद आयोजित प्रथम सत्र में पत्रिकाओं के स्वरूप और प्रस्तुति को केंद्र में रखते हुए 'जो दिखता है वही बिकता है' विषय पर विमर्श किया जाएगा, जिसमें यह विचार किया जाएगा कि साहित्यिक पत्रिकाओं के कलेवर और लेआउट में आकर्षण की कमी किस प्रकार पाठकों को उनसे दूर कर रही है और उन्हें अधिक पठनीय के साथ-साथ दर्शनीय बनाने की आवश्यकता क्यों है। दोपहर बाद के सत्रों में समागम का स्वर और अधिक व्यावहारिक तथा बहुआयामी हो जाएगा। 'थोड़ी हँसी, थोड़ी खुशी' विषयक सत्र में साहित्यिक पत्रिकाओं में कार्टून और व्यंग्य चित्रों के प्रयोग पर चर्चा होगी, जबकि अगले सत्र में पत्रिका प्रकाशन से जुड़ी प्रशासनिक और आर्थिक प्रक्रियाओं पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया जाएगा। इसमें आर.एन.आई. पंजीयन, दृश्य एवं प्रचार निदेशालय से संपर्क, डाक पंजीयन और वितरण व्यवस्था से संबंधित जटिलताओं को सरल भाषा में समझाया जाएगा। इसी क्रम में सरकारी अनुदान और विज्ञापन प्राप्त करने की प्रक्रियाओं पर भी विशेषज्ञ जानकारी साझा की जाएगी, जो विशेष रूप से छोटे और मध्यम स्तर की पत्रिकाओं के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। दिन के अंतिम चरण में साहित्यिक पत्रिकाओं की घटती प्रसार संख्या और वैश्विक स्तर पर उनके अस्तित्व पर मंडरा रहे संकट पर चर्चा करते हुए संभावित समाधान तलाशे जाएंगे, जिसके बाद सायंकालीन विशेष सत्र में देशभर से आए संपादक अपनी-अपनी पत्रिकाओं के अब तक के योगदान और अनुभव साझा करेंगे।

समागम के दूसरे दिन, 31 मार्च को, विमर्श का केंद्र साहित्यिक सामग्री की गुणवत्ता, कलात्मक प्रस्तुति और आधुनिक मुद्रण तकनीक पर रहेगा। 'छपास की भूख के बीच संपादक धर्म का चीरहरण' विषय पर आयोजित सत्र में पत्रिकाओं में प्रकाशित हो रही रचनाओं के स्तर में गिरावट और संपादकीय मानकों पर पड़ रहे प्रभावों पर गंभीर चर्चा की जाएगी। इसके पश्चात आयोजित सत्र में साहित्य और चित्रांकन के संबंधों पर विचार करते हुए यह देखा जाएगा कि चित्र और कलात्मक प्रस्तुति किस प्रकार साहित्यिक पत्रिकाओं की सौंदर्यात्मकता और पठनीयता को बढ़ा सकते हैं।

दोपहर बाद का सत्र आधुनिक मुद्रण तकनीकों और प्रकाशन के बदलते स्वरूप पर केंद्रित रहेगा, जिसमें नई तकनीकों के माध्यम से पत्रिकाओं की गुणवत्ता, प्रसार और लागत प्रबंधन पर प्रकाश डाला जाएगा। दो दिवसीय इस समागम का समापन 'पाथेय' विषयक उद्यापन सत्र से होगा, जिसमें समागम के निष्कर्षों और भविष्य की दिशा पर समग्र विचार प्रस्तुत किए जाएंगे। आयोजन समिति के अनुसार, इस समागम से प्राप्त सुझावों और निष्कर्षों को संकलित कर साहित्यिक पत्रिकाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज तैयार करने की भी योजना है। साहित्यिक पत्रकारिता के समकालीन परिदृश्य में यह आयोजन न केवल संवाद का अवसर प्रदान करेगा, बल्कि साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं के भविष्य को लेकर ठोस रणनीति बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

विश्व स्वास्थ्य...

पुनीत उपाध्याय

कागज नहीं, अब डिजिटल हेल्थ वॉलेट के इस्तेमाल को बढ़ाने पर जोर

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डबल्यूएचओ) और एलायंस फॉर हेल्थ पॉलिसी एंड सिस्टम्स रिसर्च ने टेमासेक फाउंडेशन के साथ मिलकर एक नई तीन साल की पहल शुरू की है। इसका मकसद एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस (एसियान) के सदस्य देशों को कागज़ पर आधारित हेल्थ रिकॉर्ड से हटकर सुरक्षितए आपस में जुड़ने वाले डिजिटल हेल्थ वॉलेट ; (डीएचडल्यू) अपनाने में मदद करना है। इस प्रोग्राम का मकसद राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों को मज़बूत करना, देखभाल की निरंतरता को बेहतर बनाना और यह पक्का करना है कि लोगों के पास अपनी ज़रूरी स्वास्थ्य जानकारी तक भरोसेमंद और कहीं भी इस्तेमाल हो सकने वाली पहुंच हो। टेमासेक फाउंडेशन में स्वास्थ्य और वेल.बीइंग के प्रमुख की किर्क चुएन के अनुसार कोविड महामारी ने दिखाया कि हेल्थ रिकॉर्ड का भरोसेमंद, वेरिफ़ाई करने लायक होना और लोगों के साथ सीमाओं के पार भी जा सकना कितना ज़रूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ अपनी पार्टनरशिप के ज़रिए टेमासेक फाउंडेशन उन देशों की मदद करने की उम्मीद करता है जो बिखरे हुए कागज़ी रिकॉर्ड से हटकर सुरक्षित डिजिटल हेल्थ वॉलेट अपनाना चाहते हैं जिन्हें लोग जहां भी जाएं अपने साथ ले जा सकें।

एसियान के कुछ सदस्य देशों में इस तरीके को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आज़माकर यह दिखाना है कि भरोसेमंद डिजिटल टूल कैसे स्वास्थ्य प्रणालियों को मज़बूत कर सकते हैं। देखभाल की निरंतरता को बेहतर बना सकते हैं। अगर यह कोशिश कामयाब होती है तो यह वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य मानकों को ऐसे व्यावहारिक समाधानों में बदलने में मदद कर सकती है जिनसे इस पूरे क्षेत्र के समुदायों को फ़ायदा हो सकता है। यह पहल कोविड महामारी से मिले सबकों पर आधारित है जिसने भरोसेमंद और वेरिफ़ाई करने लायक डिजिटल स्वास्थ्य दस्तावेज़ों की तत्काल ज़रूरत को दिखाया था। यह अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों (आईएचआर 2025) के भी अनुरूप है जो विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त डिजिटल स्वास्थ्य प्रमाणपत्रों की मांग करते हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन में डेटाए डिजिटल स्वास्थ्य एनालिटिक्स और एआई विभाग के निदेशक डॉण् एलेन लैब्रिक के अनुसार डिजिटल हेल्थ वॉलेट सिर्फ़ एक तकनीकी अपग्रेड से कहीं ज़्यादा हैं। वे भरोसेमंद, लोगों पर केंद्रित स्वास्थ्य प्रणालिया बनाने की एक प्रतिबद्धता हैं। देशों को सुरक्षित, इंटरऑपरेबल समाधान अपनाने में सहायता देकर हम यह सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति अपनी ज़रूरी स्वास्थ्य जानकारी आत्मविश्वास और गरिमा के साथ अपने पास रख सकें। यह साझेदारी हमारे इस साझा विश्वास को दर्शाती है कि डिजिटल बदलाव को राष्ट्रीय क्षमता को मज़बूत करना चाहिए, समानता को बनाए रखना चाहिए और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए एक नींव प्रदान करनी चाहिए। एलायंस फॉर हेल्थ पॉलिसी एंड सिस्टम्स रिसर्च के कार्यकारी निदेशक डॉ. कुमानन रसनथन बताते हैं कि डिजिटल स्वास्थ्य हस्तक्षेप तभी वास्तविक समाधान बन पाते हैं जब उन्हें स्थानीय वास्तविकताओं की सूक्ष्म समझ के आधार पर मौजूदा स्वास्थ्य प्रणालियों में सफलतापूर्वक एकीकृत किया जाता है। यह पहल वैश्विक स्तर पर मार्गदर्शन भी प्रदान करेगी ताकि अन्य देश सुरक्षित और मानकों पर आधारित डिजिटल हेल्थ वॉलेट्स को अपना सकें।

जरा हटके

अब गांवों में आटा...

डॉ. शैलेश शुक्ला

उत्तर प्रदेश के गाँवों की गूँज: प्रगति का पथ और परिवर्तन का प्रकाश

उत्तर प्रदेश की आत्मा इसके गांवों में बसती है और पिछले नौ वर्षों का कालखंड इस सत्य का साक्षी रहा है कि जब नीतिगत स्पष्टता और धरातलीय क्रियान्वयन का संगम होता है, तो दशकों की जड़ता भी गतिशीलता में बदल जाती है। 2017 से 2026 के मध्य उत्तर प्रदेश ने 'बीमारू' राज्य की छवि को पीछे छोड़ते हुए ग्रामीण विकास के उन प्रतिमानों को स्थापित किया है, जिन्हें आज नीति आयोग के 'डेल्टा रैंकिंग' और 'बहुआयामी गरीबी सूचकांक' (MPI) में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की रिपोर्टों के साथ समन्वय करते हुए भारत के गरीबी सूचकांक बताते हैं कि उत्तर प्रदेश ने करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है, जिसका सर्वाधिक लाभ ग्रामीण अंचलों को मिला है। यह परिवर्तन केवल सांख्यिकीय सुधार नहीं, बल्कि ग्रामीण जीवन के हर आयाम—चाहे वह बिजली हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो या सुरक्षा—में आया एक बुनियादी बदलाव है। ग्रामीण उत्थान की इस गाथा का सबसे दृश्य स्तंभ बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तीसरे चरण के सफल क्रियान्वयन के साथ उत्तर प्रदेश ने अपने ग्रामीण पथों को एक नई पहचान दी है। पिछले नौ वर्षों में राज्य ने लगभग 32,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण सुनिश्चित किया है। इन सड़कों ने न केवल कृषि उत्पादों के लिए 'फार्म-टू-मार्केट' पहुंच को सुगम बनाया, बल्कि ग्रामीण युवाओं के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने की बाधाओं को भी समाप्त किया है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में मंडी परिषद् और लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों का जाल सुदूरवर्ती मजरों को जिला मुख्यालयों से जोड़ रहा है। परिवहन की इस सुगमता ने रसद (Logistics) लागत को कम

किया है, जिससे छोटे किसानों की शुद्ध आय में वृद्धि दर्ज की गई है।

ऊर्जा के क्षेत्र में 'सौभाग्य योजना' और 'दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना' ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण परिदृश्य का अंधेरा छटा दिया है। राज्य सरकार के ऊर्जा सुधारों के फलस्वरूप आज गांवों को रोस्टर के अनुसार 18 घंटे की निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल रही है। यह आंकड़ा पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में लगभग दोगुना है। बिजली की इस उपलब्धता ने केवल प्रकाश ही नहीं फैलाया, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विविधीकरण का मार्ग प्रशस्त किया है। अब गांवों में आटा चक्की, वेल्डिंग यूनिट और लघु प्रसंस्करण इकाइयां डीजल जनरेटरों के बजाय सस्ती बिजली पर चल रही हैं। इसके अतिरिक्त, 'कुसुम योजना' के माध्यम से सोलर पंपों के वितरण ने सिंचाई की लागत को न्यूनतम किया है, जिससे किसान अब पारंपरिक फसलों के स्थान पर नकदी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। स्वच्छता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आई क्रांति इस कालखंड की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। 'स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)' के तहत उत्तर प्रदेश ने दो करोड़ से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण कर स्वयं को खुले में शौच मुक्त घोषित किया और अब 'ओडीएफ प्लस' की दिशा में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर कार्य कर रहा है। इन 'इज्जत घरों' ने न केवल स्वास्थ्य सुधारों में भूमिका निभाई, बल्कि ग्रामीण महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा को एक नया आयाम दिया। इसी क्रम में 'जल जीवन मिशन' के अंतर्गत 'हर घर जल' योजना ने बुंदेलखंड और विंध्य जैसे जल-संकट वाले क्षेत्रों में जीवन को सरल बनाया है। आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में नल कनेक्शन देने की गति देश में सर्वाधिक रही है, जिससे दूषित जल से होने वाली बीमारियों, जैसे जापानी इंसेफेलाइटिस (JE) और एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (AES) के मामलों में 95 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है।

खोज समाधान की

इस धरा पर कोई ऐसा नहीं हैं जिसको कोई न कोई समस्या नहीं हों। वह यह भी है कि पृथ्वी पर ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं हैं । वह कुछ लोग समस्या को कुछ ज्यादा ही ओढ़ लेते हैं। उनसे हतभागी कोई नहीं यह सोच-सोच कर वह मायूस भी होते रहते हैं। हम जिस युग में जी रहें है वह द्वन्दों से भरा हुआ हैं । हमारे जीवन का हर क्षेत्र चाहे वह सामाजिक हों, आर्थिक हों या मानसिक किसी न किसी रूप में संघर्ष और जटिलता से वह जूझ रहा हैं । यह सृष्टि का स्वाभाविक नियम हैं । जहां द्वन्द हैं वहां समस्या अनिवार्य रूप से उपस्थित होती हैं । मनुष्य ने बार- बार इस धरती को समस्यामुक्त बनाने का प्रयास किया किन्तु ऐसा कभी संभव नहीं हुआ और न ही भविष्य में होगा । वह इसका कारण यह हैं कि जब तक मतभेद, इच्छाएं , विचार और आकांक्षाएं आदि हैं तब तक संघर्ष और असंतुलन बना रहेगा । अब प्रश्न यह नहीं हैं कि समस्याएं क्यों हैं बल्कि यह हैं कि उनका सामना हमारें द्वारा किस दृष्टि से किया जाता हैं । हमारा अत्यधिक चिंतन बेकार में और ज्यादा समस्याएं पैदा करता है।हम कोई भी परिस्थिति हो हमेशा विधायक चिंतन से धैर्यपूर्वक उसका समाधान खोजने की सोचे गुरुदेव तुलसी की अमृतमयी वाणी हमेशा हमारी स्मृति में रहे कि सदा विधेयात्मक चिंतन रहे । हम क्यों निषेधात्मक भावों में उलझे। हमारा भावशुद्धि से चिंतन विवेक पूर्ण सही सोचने की शक्ति प्रदान करता है।हम कभी भी किसी भी परिस्थिति में सम रहते हुए अपने देव,गुरु और धर्म की शरण पर दृढ़ आस्था रखे तो कभी भी अत्यधिक चिंतन में नहीं उलझते , शांतचित रहते हैं । वह समस्याओं से भागने या उन्हें नकारने की बजाय हमारे द्वारा उनका समाधान खोजना ही जीवन की सच्ची कला हैं । बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार की समस्याएं हम मनुष्य के अस्तित्व का हिस्सा हैं । बाहर की दुनिया में अभाव, रोग, असुरक्षा और प्रतिस्पर्धा आदि जैसी चुनौतियां हैं । वह हमारे भीतर की दुनिया में लोभ, क्रोध, वासना, घृणा और छल - कपट आदि जैसी प्रवृत्तियां रहती हैं । बाह्य जगत की समस्याओं को हम मनुष्यों ने खेती, विज्ञान, उद्योग और चिकित्सा आदि के माध्यम से काफी हद तक सुलझाने का हमने प्रयास किया हैं । हमारे भीतर की अशांति आज भी हमको अस्थिर बनायें हुए हैं । हमने भीतर की समस्याओं के समाधान के लिए धर्म और अध्यात्म का मार्ग अपनाया हैं । धर्म का उद्देश्य केवल पूजा या अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और चेतना की जागृति हैं । वह ध्यान इस प्रक्रिया का सबसे प्रभावशाली साधन हैं । समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते ही मिलते हैं । वह हल निकलते ही निकलते हैं। हम खुद निराश रहेंगे तो समस्या को और हावी होने का न्यौता देंगे। जिन्दगी किसी की भी आसान नहीं है।

› प्रदीप छाजेड़

आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वालों में महेंद्र सिंह धोनी पहले पायदान पर हैं। वे अब तक 278 मैच खेल चुके हैं। चेन्नई सुपर किंग्स को पांच बार खिताब जिताया है। 38.30 की औसत से 5439 रन बनाए हैं। इस दौरान धोनी ने 24 अर्धशतक भी लगाए हैं। उन्होंने विकेटकीपिंग में 47 स्टंपिंग और 154 कैच भी लपके हैं।

मांसपेशियों में खिंचाव, सीएसके ने पोस्ट में जानकारी दी

2 हफ्ते आईपीएल से बाहर रह सकते हैं धोनी

नई दिल्ली। एमएस धोनी IPL 2026 के शुरुआती दो हफ्ते बाहर रह सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के पूर्व कप्तान इस समय मांसपेशियों में खिंचाव के कारण रिहैब से गुजर रहे हैं। CSK की ओर से एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्हें काफ स्ट्रेन, यानी पिंडली में खिंचाव है।

धोनी फिलहाल 44 साल के हैं। वे IPL 2026 के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। पिछले सीजन ऋतुराज गायकवाड के चोटिल होने के बाद उन्हें बीच में ही चेन्नई की कप्तानी करनी पड़ी। उन्होंने टीम को 4 में से 3 मैचों में जीत दिलाई थी।

धोनी IPL में 100 मैच जीतने वाले एकमात्र कप्तान हैं। उन्होंने IPL में सबसे ज्यादा 235 मैचों में कप्तानी की है। धोनी अपनी कप्तानी में टीम को 136 मैचों में जीत दिला चुके हैं, जबकि 97 में टीम को हार मिली। धोनी ने अपनी कप्तानी में CSK को 2023 में आखिरी बार चैंपियन बनाया था। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा हैं। उन्होंने 158 मैचों में कप्तानी की है और 87 मैच जीते हैं।

धोनी ने IPL 2023 के फाइनल के बाद 1 जून को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में घुटने की सर्जरी कराई थी। धोनी का ऑपरेशन डॉक्टर दिनशॉ पारदीवाला ने किया था।

3 मैचों से हो सकते हैं बाहर

अगर धोनी पूरे 2 हफ्ते यानि 14 दिन तक बाहर रहते हैं तो वो कम से कम 3 मैच नहीं खेल पाएंगे। CSK का पहला मैच 30 मार्च को गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ है। इसके बाद उसका अगला मैच 3 अप्रैल को चेन्नई में पंजाब किंग्स के खिलाफ है।

टीम अपना तीसरा मैच 5 अप्रैल को डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ उसके ही घर में खेलेगी, जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। धोनी इन तीनों ही मैच से बाहर रह सकते हैं। उनकी वापसी 11 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबले में हो सकती है।

धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट से साल 2020 में संन्यास ले चुके हैं। उनके IPL रिटायरमेंट की अटकलें 2023 से ही लगाई जा रही हैं। ऐसा माना जा रहा था कि साल 2026 धोनी का आखिरी साल होगा।

मैदान पर उतरते ही ईशान किशन के नाम होगा बड़ा रिकॉर्ड

नई दिल्ली। आईपीएल-2026 की शुरुआत आज से हो रही है। सीजन के पहले मैच में मौजूदा विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इस मैच में हैदराबाद की कप्तानी युवा बल्लेबाज ईशान किशन करेंगे क्योंकि पैट कमिंस चोट के कारण कुछ मैचों से बाहर हैं। किशन जैसी ही मैदान पर उतरेंगे वैसे ही अपने नाम एक रिकॉर्ड कर लेंगे। कमिंस को पीठ में चोट है जिसके कारण वह शुरुआती कुछ मैचों से बाहर हो सकते हैं। हालांकि, वह टीम के साथ हैं और सफर कर रहे हैं। ईशान ने अपनी कप्तानी में झारखंड को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिताई थी। इस मैच में कप्तानी करने के साथ ही ईशान अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड कर लेंगे। वह हैदराबाद के लिए आईपीएल में कप्तानी करने वाले सबसे युवा कप्तान होंगे। ईशान इस समय 27 साल 253 दिनों के हैं। वहीं वह ओवरऑल फ्रेंचाइजी के दूसरे सबसे युवा कप्तान होंगे। इस मामले में न्यूजीलैंड के केन विलियम-सन पहले नंबर पर है जिन्होंने साल 2018 में 27 साल 244 दिनों के थे।

मरियम नवाज पर तंज करना नसीम शाह को पड़ा भारी

पीसीबी ने लिया कड़ा एक्शन

नई दिल्ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने अपने तेज गेंदबाज नसीम शाह की एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्हें नोटिस दिया है। नसीम ने बाद में ये पोस्ट हटा ली थी लेकिन फिर भी पीसीबी ने उनसे सफाई पेश करने को कहा है। तेज गेंदबाज ने ये पोस्ट पंजाब की महिला मुख्यमंत्री मरियम नवाज को लेकर लिखी थी।

नसीम ने अपनी पोस्ट में मरियम पर तंज कसते हुए उन्हें क्वीन कहा था और इसी लेकर पीसीबी भड़क गया है। नसीम इस समय पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) में रावलपिं-डीज के लिए खेल रहे हैं। इस मामले के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं।

पीसीबी ने कहा है कि उसने नसीम के खिलाफ अनुशासनहिनता के संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी है। पीसीबी ने अपने बयान में कहा, इनसीम शाह को तय समय सीमा में

अपना जवाब पेश करना होगा। पीसीबी पेशेवर मानकों, अनुबंध के नियम और खेल की अखंड़ता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

पीसीबी ने अपने बयान में मामले को या फिर नसीम द्वारा तोड़ गए नियम के तहत क्लॉज का जिक्र नहीं किया है। नसीम पाकिस्तान के उभरते हुए गेंदबाज हैं, लेकिन उनकी हरकत पर पीसीबी कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं हैं।

मरियम नवाज लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पीएसएल के पहले मैच में बतौर मेहमान आईं थी और पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने उनका स्वागत किया था।

पेट के इंफेक्शन से बिगड़ी हालत, 14 दिन में 4 किलो वजन घटा

ऋतिक की गर्लफ्रेंड सबा आजाद अस्पताल में एडमिट

नई दिल्ली, एजेंसी

बॉलीवुड एक्ट्रेस सबा आजाद ने अस्पताल से अपनी तस्वीर शेयर कर बताया कि उन्हें इंफेक्शन हो गया था, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई। सबा ने शुक्रवार को इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, "मेरी जिंदगी के सबसे खराब 14 दिन। साइक्लोस्पोरा कैटेनेन्सिस, तुम सच में बहुत खतरनाक हो! मैं हमेशा घर का खाना खाती हूं, हर जगह अपनी पानी की बोतल लेकर चलती हूं, फिर भी ये पेट का इंफेक्शन अचानक हो गया। वो भी साल के सबसे व्यस्त समय में।"सबा ने आगे लिखा, "दो हफ्तों में मेरा 4 किलो वजन कम हो गया, जो पहले से ही ज्यादा नहीं था। हालत ऐसी है कि ठीक से चल भी नहीं पा रही हूं। एक दिन मैं दिन में दो बार ट्रेनिंग कर रही थी, पुल-अप्स और भारी वेट उठा रही थी और अगले ही दिन इतनी कमजोर हो गई कि एक टूथपिक तक उठाने की ताकत नहीं बची। इसलिए प्लीज, अपने पेट का ध्यान रखें। सलाद और सब्जियों को अच्छे से धोएं, जैसे आपकी जिंदगी उसी पर निर्भर हो, क्योंकि कभी-कभी सच में होती है!"

लास्ट में सबा ने बताया कि उनकी तस्वीर ऋतिक रोशन ने ली, जो मेरे खराब मूड में भी हंसी ढूंढ लेते हैं। साथ ही मजाकिया अंदाज में लिखा, "मैं जितनी दिख रही हूं, उतनी दुबली नहीं हुई हूं, बेड बड़ा है और एगल वाइड है।"

वर्कफ्रंट की बात करें तो ऋतिक जल्द डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू करने वाले हैं। वे 'क्रिश 4' को डायरेक्ट कर रहे हैं और साथ ही प्राइम वीडियो की 'स्टॉर्म' नाम की वेब सीरीज भी बना रहे हैं।

वहीं सबा बॉबी देओल के साथ फिल्म 'बंदर' में नजर आएंगी।

सबा 2021 से ऋतिक को डेट कर रही हैं

ऋतिक और सबा 2021 से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों को डिनर डेट्स और करण जौहर की 50वीं बर्थडे पार्टी में साथ देखा गया, जिसके बाद उनके रिश्ते की चर्चा सोशल मीडिया पर हुई थी। इसके बाद दोनों ऋतिक की एक्स वाइफ सुजैन और उनके बॉयफ्रेंड अर्सलान गोनी के साथ भी नजर आए। अर्सलान और सुजैन भी 2022 से डेट कर रहे हैं।

धुरंधर 2 को असदुद्दीन ओवैसी ने बताया बकवास

'ये कोई फिल्म है'

नई दिल्ली। लोकसभा सांसद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष, असदुद्दीन ओवैसी को आदित्य धर निर्देशित फिल्म धुरंधर 2 कुछ खास पसंद नहीं आई।

एक शिखर सम्मेलन में बातचीत के दौरान उन्होंने फिल्म को 'बकवास' बताया और इसकी आलोचना की। ओवैसी ने कहा कि इस तरह की फिल्में हिंसा को बढ़ावा देती हैं।

टाइम्स समिट में बातचीत के दौरान जब ओवैसी से धुरंधर को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा- 'पिक्चर है वो? तीन घंटे बकवास। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं तीन घंटे की फिल्म देखूं। मैं बस इतनी आशा करता हूं कि मैं जब एक घंटे बोलूं तो लोग मुझे सुनें।'

उन्होंने आगे कहा- 'इस फिल्म में गाली-गलौज और हिंसा को बढ़ावा देने के अलावा और क्या है? तीन घंटे देखने के बाद तो मन में यह सवाल उठता है कि क्या मुसलमानों को गाली देना जरूरी है या नहीं। भला किसके पास इतना समय है यह सब देखने का?' जब होस्ट ने उनसे फिर कहा कि दुनिया फिल्म देख रही है और उन्हें पसंद आ रही है। इस पर ओवैसी बोले- 'हम हैदराबाद में बोलते हैं कि प्यारे इन चीजों को दिल पर मत लो, मुर्दे पर लो। तो हम मुर्दे पर लेकर छोड़ देते हैं उसको।'

बता दें कि तमाम आलोचना के बावजूद धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 716 करोड़ रुपये और 9 दिन में दुनियाभर में 1100 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। आदित्य धर द्वारा लिखित और निर्देशित, धुरंधर फिल्मों का निर्माण ज्योति देशपांडे, आदित्य और लोकेश धर द्वारा जियो स्टूडियोज और बी62 स्टूडियोज के बैनर तले किया गया है।

अनीत पड्डा की बहन रीत ने धुरंधर 2 को बताया प्रोपेगैंडा

नई दिल्ली। एक्ट्रेस अनीत पड्डा की बहन रीत ने धुरंधर 2 को प्रोपेगैंडा फिल्म बताया और एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की ऑस्कर सेरेमनी के दौरान युद्ध मुद्दे पर चुप्पी की आलोचना की। दरअसल, इंस्टाग्राम पर एक यूजर ने रीत के पहले के पोस्ट और राजनीतिक मुद्दों पर उनके रुख पर सवाल किया गया था। जिसके बाद रीत ने जवाब देते हुए लिखा कि वह आमतौर पर सोशल मीडिया पर बहस में शामिल नहीं होतीं, लेकिन इस बार उन्होंने हर मुद्दे पर अपनी बात रखने का फैसला किया। रीत ने कहा कि धुरंधर 2 सरकार के पक्ष में एक नैरेटिव दिखाती है और इसमें राजनीतिक भाषणों के जरिए नोटबंदी जैसे फैसलों को सही ठहराने की कोशिश की गई है।

उन्होंने द कश्मीर फाइल्स और द केरल स्टोरी पर भी सवाल उठाए। रीत के मुताबिक इन फिल्मों में दिखाए गए आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए हैं, जो एक समुदाय के खिलाफ नैरेटिव बनाने का काम करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब '95 जैसी फिल्में, जो अलग राजनीतिक दृष्टिकोण दिखाती हैं, उन्हें रिलीज में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

फास्ट न्यूज

सोना इस हफ्ते 4,276 सस्ता, 1.43 लाख पर आया

नई दिल्ली । इस हफ्ते सोने-चांदी के दाम में गिरावट रही। सोना हफ्तेभर में 4,276 रुपए गिरकर 1.43 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं, चांदी 2.32 लाख किलो से गिरकर 2.21 लाख रुपए पर पहुंच गई है। अमेरिका-इजराइल की ईरान से चल रही जंग की वजह से निवेशक अपनी 'गोल्ड होल्डिंग्स' बेचकर कैश (डॉलर) इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि बाजार की अस्थिरता से निपट सकें। इससे डॉलर डिमांड बढ़ रही है और सोने-चांदी के दाम गिर रहे हैं।

पांच महिलाएं, 29 साल का सबसे कम उम्र का मंत्री

नई दिल्ली। नेपाल में बालेन युग की शुरुआत हो गई है। शुक्रवार को काठमांडू में राष्ट्रपति कार्यालय में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने बालेंद्र शाह उर्फ बालेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बालेंद्र शाह के साथ कई प्रमुख विभागों के मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। रैपर से नेता बने 35 वर्षीय बालेन नेपाल के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। उनके शपथ ग्रहण समारोह में हिंदू-बौद्ध परंपराओं का मिश्रण देखने को मिला। बालेन सरकार की सबसे खास बात यह है कि इतनी मंत्रिपरिषद की औसत उम्र लगभग 35 वर्ष है। नेपाल के राजनीतिक इतिहास में यह अब तक की सबसे युवा कैबिनेट बताई जा रही है।

अमेरिका-ईरान के बीच जंग में अब यमन की एंट्री

नई दिल्ली। अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग में अब यमन की एंट्री हो गई है। हूतियों ने इजरायल पर हमला किया है। यमन से बैलिस्टिक मिसाइल हमले के कारण दक्षिणी इजरायल के बीरशेबा और आस-पास के कस्बों में सायरन बज उठे। टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मौजूदा युद्ध में ईरान समर्थित हूतियों द्वारा इजरायल पर किया गया पहला हमला है। सेना का कहना है कि उसने यमन से मिसाइल लॉन्च की पहचान कर ली है और इस खतरे को रोकने के लिए काम कर रही है।

ईरान जंग के बीच ट्रम्प ने दिया बयान कब्जे के लिए सेना का इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले कह चुके- हासिल करके रहूंगा

'अगला नंबर क्यूबा का'

बयान

वॉशिंगटन डीसी, एजेंसी

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अब अगला नंबर क्यूबा का है। यह बात उन्होंने शुक्रवार को मियामी में एक बिजनेस समिट के दौरान कही।

ट्रम्प ने हालांकि साफ तौर पर यह नहीं बताया कि क्यूबा के खिलाफ उनका अगला कदम क्या होगा, लेकिन उन्होंने इशारा दिया कि जरूरत पड़ी तो सैन्य ताकत का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।

ट्रम्प ने कहा-मैंने अमेरिकी सेना को बहुत मजबूत बनाया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन कभी-कभी ऐसा करना पड़ता है। वैसे क्यूबा का अगला नंबर है।

15 मार्च को पत्रकारों से क्यूबा के बारे में बात करते हुए ट्रम्प

हालांकि इसके तुरंत बाद ही उन्होंने कहा- ऐसा समझो कि मैंने यह कहा ही नहीं है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे क्यूबा को आजाद कर सकते हैं या अपने कब्जे में ले सकते हैं, और उनके पास कुछ भी करने की क्षमता है। 1898 में स्पेन-अमेरिका युद्ध के बाद क्यूबा स्पेन से आजाद हुआ, लेकिन असली कंट्रोल अमेरिका के हाथ में चला गया।

क्यूबा में निवेश का मौका बनाना चाहते हैं ट्रम्प

ट्रम्प के बयान से यह भी साफ होता है कि वह क्यूबा को सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि कारोबारी नजरिए से भी देख रहे हैं। वह पहले से ही इस द्वीप में निवेश की संभावना देखते रहे हैं। 1998 में उनकी कंपनी ने चुपचाप क्यूबा का दौरा कराया था। 2011-12 में भी उनके संगठन के लोग वहां गोल्फ कोर्स बनाने की संभावनाएं देख चुके हैं। 2016 के चुनाव प्रचार के दौरान भी ट्रम्प ने कहा था कि क्यूबा निवेश के लिए अच्छा मौका हो सकता है। अब उन्होंने फिर कहा, "वे हमसे बात कर रहे हैं। यह एक असफल देश है। उनके पास न पैसा है, न तेल, कुछ भी नहीं है।"

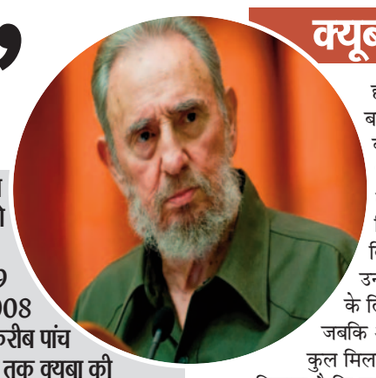

फिदेल कास्त्रो ने 1959 से 2008 तक करीब पांच दशक तक क्यूबा की कमान संभाले रखी।

क्यूबा से बातचीत जारी है

हालांकि इतनी सख्त बातें कहने के बावजूद, अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि बातचीत के रास्ते अभी भी खुले हैं और क्यूबा के नेताओं से बातचीत जारी है। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज-कैनल ने भी माना है कि अमेरिका से बातचीत हो रही है। उन्होंने संकेत दिया कि टकराव से बचने के लिए क्यूबा बातचीत करना चाहता है, जबकि अमेरिका का दबाव बढ़ता जा रहा है। कुल मिलाकर, ट्रंप का क्यूबा पर फोकस दिखाता है कि उनकी विदेश नीति अब ज्यादा आक्रामक और सीधे संदेश देने वाली हो गई है।

क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज कानेल इस महीने में पहले भी कह चुके हैं कि क्यूबा ने अमेरिकी सरकार के साथ बातचीत की है।

तेल सप्लाई रोक चुका है अमेरिका

असल में, अमेरिका पहले से ही क्यूबा पर दबाव बना रहा है। जनवरी से अमेरिका ने क्यूबा को हो रही तेल सप्लाई को लगभग रोक दिया है। दूसरे देशों को भी चेतावनी दी जा रही है कि वे क्यूबा को तेल न दें। हाल ही में अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने कोलंबिया से क्यूबा जा रहे एक तेल टैंकर को भी रोक लिया। इसका असर क्यूबा में साफ दिख रहा है। 9 जनवरी के बाद से वहां कोई बड़ी तेल सप्लाई नहीं पहुंची है। वहां हालात तेजी से खराब हो रहे हैं। क्यूबा के ब्लैक मार्केट में पेट्रोल करीब 35 डॉलर प्रति गैलन तक पहुंच गया है रोजाना बिजली कट रही है, सोमवार को पूरे देश में ब्लैकआउट हुआ। अस्पतालों में सर्जरी टल रही हैं। दवाइयों की कमी हो रही है और खाने की समस्या बढ़ रही है। इन हालात में क्यूबा की सरकार पर दबाव बढ़ गया है।

आर्थिक संकट से जूझ रहा है क्यूबा

ट्रम्प का यह बयान ऐसे समय में आया है जब क्यूबा गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वेनेजुएला से तेल सप्लाई बंद होने के बाद वहां ईंधन की भारी कमी हो गई है, जिससे हालात और खराब हो गए हैं।

अमेरिका की मदद से हुई कार्रवाई के बाद वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को हटाया गया, जिससे क्यूबा की बड़ी ऊर्जा सप्लाई कट गई। ट्रम्प पहले भी कह चुके हैं कि क्यूबा की सरकार गिरने के करीब है और उन्होंने 'फ्रेंडली टेकओवर' (दोस्ती के नाम पर कब्जा) की बात भी की है। इस महीने की शुरुआत में उन्होंने कहा था कि यह 'फ्रेंडली टेकओवर' हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें 'सम्मान' मिलेगा अगर वे किसी रूप में क्यूबा को अपने नियंत्रण में ले लें।

फैसला : 1 अप्रैल से लागू ■ भारत पर कम, चीन-तुर्किये और ब्राजील पर ज्यादा असर

रूस ने 4 महीने के लिए पेट्रोल निर्यात रोका

मॉस्को, एजेंसी

रूस ने 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक पेट्रोल निर्यात पर रोक का फैसला किया है। उप-प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने ऊर्जा मंत्रालय से इस प्रस्ताव को तैयार करने को कहा। रूस के मुताबिक यह कदम घरेलू सप्लाई बनाए रखने और कीमतें नियंत्रित रखने के लिए है।

नोवाक ने कहा कि मिडिल ईस्ट में चल रहे इजराइल-ईरान जंग की वजह से ग्लोबल तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्शन बाजार में अस्थिरता बढ़ी है। इससे कीमतों में उतार-चढ़ाव हो रहा है। रूस रोजाना 1.2 से 1.7 लाख बैरल पेट्रोल निर्यात करता है।

इस फैसले से चीन, तुर्किये, ब्राजील, अफ्रीका और सिंगापुर प्रभावित हो सकते हैं। ये देश रूसी तेल उत्पादों के बड़े खरीदार हैं। भारत पर असर कम होगा क्योंकि वह पेट्रोल नहीं, कच्चा तेल खरीदता है।

रूस पहले भी कीमत नियंत्रण और घरेलू सप्लाई के लिए पेट्रोल-डीजल निर्यात पर रोक लगा चुका है। पिछले साल भी ऐसा हुआ था, जब यूक्रेन हमलों से रिफाइनरियां प्रभावित हुई थीं। इंडस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक, रूस ने पिछले साल करीब 50 लाख मीट्रिक टन पेट्रोल एक्सपोर्ट किया था, यानी हर दिन लगभग 1.17 लाख बैरल के बराबर है। एक दिन पहले ही नोवाक ने कहा था कि जरूरत पड़ी तो रूस फिर से तेल निर्यात पर रोक लगा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि रूस का यूराल्स तेल और दूसरे तेल उत्पाद इन दिनों ब्रेंट क्रूड के बराबर या उससे भी महंगे दाम पर बिक रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत सीधेतौर पर पेट्रोल जैसे तैयार ईंधन पर ज्यादा निर्भर नहीं है, बल्कि कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) पर निर्भर है। क्रूड ऑयल को ही रिफाइन कर पेट्रोल और डीजल बनाए जाते हैं। भारत अपनी जरूरत का करीब 80% कच्चा तेल आयात करता है, जिसमें से लगभग 20% रूस से आता है।

पहले भी पेट्रोल एक्सपोर्ट पर रोक लगाई गई थी

मॉस्को में शुक्रवार को पेट्रोल एक्सपोर्ट के बैन को लेकर बैठक हुई थी। इसमें खासतौर पर यह जोर दिया गया कि राष्ट्रपति पुतिन ईंधन कीमतें नियंत्रित रखना चाहते हैं।

मंत्री नोवाक ने बैठक में कहा कि पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त स्टॉक है और रिफाइन-रियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। तेल कंपनियों ने कहा कि पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त स्टॉक है और रिफाइनरियां पूरी या उससे अधिक क्षमता पर काम कर रही हैं, जिससे जरूरत पूरी हो रही है।

रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने शुक्रवार को देश में पेट्रोल और दूसरे तेल उत्पादों की उपलब्धता और कीमतों की स्थिति की समीक्षा की।

अबू धाबी में फटी ईरान की मिसाइल, मलबा गिरने से पांच भारतीय घायल

नई दिल्ली, एजेंसी

शनिवार को यूएई में अबू धाबी के खलीफा इकोनॉमिक जोन (KEZAD) के पास एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोके जाने के बाद गिरे मलबे से पांच भारतीय नागरिक घायल हो गए।

अबू धाबी मीडिया ऑफिस के अनुसार, यह घटना KEZAD के आस-पास तब हुई जब हवाई सुरक्षा प्रणालियों ने आने वाली मिसाइल को सफलतापूर्वक रोक लिया, जिसके कारण उस इलाके में मलबा गिर गया। अधिकारियों ने पुष्टि की कि इस घटना के बाद पांच लोग घायल हुए, जिन्हें मामूली चोटें आई हैं।

बयान में कहा गया, रखलीफा इकोनॉमिक जोन अबू धाबी (KEZAD) के आस-पास पहले बताई गई घटना के संबंध में चल रही जांच के तहत, जो हवाई सुरक्षा प्रणालियों द्वारा एक बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक रोके जाने के बाद गिरे मलबे के कारण हुई थी। अधिकारी पुष्टि करते हैं कि

- अबू धाबी में बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक रोका गया।
- मिसाइल के मलबे से पांच भारतीय नागरिक घायल हुए।
- घायलों को मामूली से मध्यम चोटें आई हैं।

इस घटना के परिणामस्वरूप भारतीय नागरिकता वाले पांच लोगों को मामूली से लेकर मध्यम दर्जे की चोटें आई हैं।

अधिकारियों ने जनता से आग्रह किया कि वे केवल सत्यापित जानकारी पर ही भरोसा करें और अफवाहें फैलाने से बचें।

आईफोन-15 और 16 जैसे पुराने मॉडल्स 5,000 तक महंगे होंगे

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत में अब पुराने आईफोन खरीदने पर ग्राहकों को ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। एपल ने आईफोन 15 और 16 जैसे पुराने मॉडल्स पर रिटेलर्स को डिमांड जनरेशन (DG) सपोर्ट यानी इंसेंटिव देना बंद करने का फैसला किया, जिससे कीमतें करीब 5,000 रुपए तक बढ़ सकती हैं।

मनीकंट्रोल के मार्केट एक्सपर्ट्स के अनुसार, यह फैसला इसी हफ्ते लागू हो सकता है। हाल ही में कैशबैक ऑफर्स 6,000 से घटाकर 1,000 रुपए किए गए थे, जिससे आईफोन 17 सीरीज महंगी हुई और अब पुराने मॉडल्स की कीमतें भी बढ़ जाएंगी।

मार्केट सोर्सेज के मुताबिक, डिमांड जनरेशन यानी DG सपोर्ट एक इंसेंटिव है जो ब्रांड्स रिटेलर्स और चैनल पार्टनर्स को देते हैं, जिससे वे ग्राहकों को डिस्काउंट देकर डिमांड बढ़ाते हैं। MRP बदले बिना भी इस सपोर्ट से फोन सस्ते मिलते थे। अब सपोर्ट बंद होने से रिटेलर्स पहले जैसा डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे और ग्राहकों का फाइनल बिल बढ़ेगा।

पार्षद बोले- हफ्ते में 2 दिन नहीं मिल रहा डीजल, एलएसए ने लिखा- इमरजेंसी में ईंधन दिलाएं

डंपिंग यार्डों से कूड़ा उठान में देरी

मांग

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ में घर-घर कूड़ा कलेक्शन के बाद डंपिंग यार्डों (कूड़ा घरों) में कूड़ा जमा हो रहा है। यहां से कूड़ा उठान में देरी हो रही है। कई पार्षदों को कहना है कि नगर निगम से हफ्ते में 2 दिन डीजल नहीं मिल रहा है। शहर के 5 जोन में सफाई व्यवस्था संभाल रही कार्यदायी संस्था LSA (लखनऊ स्वच्छता अभियान) ने नगर आयुक्त को एक लेटर भी लिखा है।

इसके जरिये उसने मांग की है कि संस्था को इमरजेंसी सर्विस के तौर पर समय से ईंधन उपलब्ध कराया जाए, ताकि सेवा लगातार चलती रहे। हालांकि, नगर आयुक्त गौरव कुमार ने स्पष्ट किया है कि ईंधन की कमी नहीं है। शहर की हर व्यवस्था निर्बाध चलती रहेगी। बता दें कि डीजल-पेट्रोल खत्म होने की अफवाह के चलते पेट्रोल पंपों पर भीड़ लग रही है। नगर निगम के कई पार्षदों का कहना है कि कई बार अधिकारियों से शिकायत की कि शनिवार और रविवार को गाड़ियों को डीजल नहीं मिल रहा है। इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस वजह से कूड़ा घरों में भारी मात्रा में कूड़ा पड़ा रह रहा है।

हालांकि, आरआर विभाग के चीफ इंजीनियर मनोज प्रभात का कहना है कि कोई ऐसी समस्या नहीं है। प्राथमिकता के आधार पर शहर में काम किया जा रहा है।

मेयर सुषमा खर्कवाल ने कहा कि शहरवासियों से अपील है कि शहर में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाद्य सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता है। किसी भी प्रकार की कमी नहीं है।

एलएसए का लेटर-संस्था की तरफ से कूड़ा उठान और साफ-सफाई का काम किया जाता है। गाड़ियों में पेट्रोल डीजल की कमी न हो। इसके लिए हमें इमरजेंसी सर्विस के तौर पर पेट्रोल-डीजल की व्यवस्था समय से कराई जाए ताकि कोई समस्या न आए।

कई विभागों को डीजल मिलने में हो रही देरी

नगर निगम के अभियंत्रण, उद्यान, पशु पालन सहित अन्य विभागों को भी नगर निगम की तरफ से डीजल दिया जाता है। विभागों के पास में कुल करीब 450 गाड़ियां हैं। इनके जरिये करीब आठ से नौ हजार लीटर ईंधन एक दिन में खर्च हो जाता है।

आरआर विभाग का मुख्यालय खाली होने के बाद नगर निगम की तरफ से जोन-1 और जोन- 8 में स्थित पेट्रोल पंप से तेल लेने की व्यवस्था की गई है। इस बीच पशु पालन, उद्यान विभाग, विज्ञापन विभाग के लोगों का भी कहना है कि तेल मिल रहा है, लेकिन देर से।

पार्षदों ने बताई समस्या, नहीं सुन रहे अधिकारी

अचार्य नरेंद्र देव वार्ड के पार्षद मनीष रस्तोगी ने बताया कि शनिवार और रविवार को डीजल देना बंद हो गया है। इससे तीन चार राउंड में साफ होने वाला कूड़ा घर अब कई दिनों तक भरा रहता है। शिकायत के बाद भी अधिकारी नहीं सुन रहे। पार्षद प्रतिनिधि संतोष राय ने कहा कि डीजल मिलने में देरी हो रहा है। इससे पूरे वार्ड में समस्या हो रही है। कूड़ा उठान दो से तीन दिनों तक नहीं हो रहा है। शनिवार और रविवार को डीजल नहीं दे रहे हैं। सड़क का कूड़ा उठाने में दिक्कत हो रही है। जोनल सिनेटरी अधिकारी और जोनल अधिकारी के पास में कोई पावर नहीं है। ऐसे में समस्या बढ़ रही है। बशीरतगंज गणेशगंज वार्ड से पार्षद गिरीश गुप्ता ने कहा कि सुपरवाइजर परेशान हैं।

पीजीआई में 2314 पदों पर भर्ती को मंजूरी

614 डॉक्टरों की नियुक्ति होगी

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ । राजधानी लखनऊ स्थित संजय गांधी पीजीआई में बड़े स्तर पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। गवर्निंग बॉडी की बैठक में कुल 2314 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसमें 614 डॉक्टरों के साथ ही बड़ी संख्या में नर्सिंग और टेक्नीशियन स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। यह भर्ती संस्थान में बन रहे एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर के संचालन के लिए की जा रही है। मंजूरी के अनुसार, संस्थान में कुल 614 डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। इसमें 131 सीनियर डॉक्टर और 483 रेजिडेंट डॉक्टर शामिल हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 1540 नर्स और टेक्नीशियन पदों को भी भरने की स्वीकृति दी गई है। साथ ही 160 आउटसोर्सिंग पदों पर भी भर्ती होगी। पीजीआई परिसर में बन रहे देश के पहले एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर के लिए यह भर्ती की जा रही है। करीब 500 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रहा यह सेंटर अपने पहले चरण में लगभग 90% तक पूरा हो चुका है। इस सेंटर में बच्चों से जुड़ी गंभीर बीमारियों के इलाज की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यहां सुपर स्पेशियलिटी कोर्स भी संचालित किए जाएंगे, जिससे विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार किए जा सकेंगे। अधिकारियों के मुताबिक, सेंटर में 24 विभाग स्थापित किए जाएंगे और हर साल बड़ी संख्या में बाल रोग विशेषज्ञ तैयार किए जाएंगे। इससे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी।

नर्सिंग-टेक्नीशियन के भी 1540 पद भरेंगे

फास्ट न्यूज

गांव में घरेलू बिजली कनेक्शन से दुकान चलाने वालों को मिले राहत

लखनऊ। ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू कनेक्शन वाली बिजली का ही घर में बनी दुकान में इस्तेमाल करने की सशर्त अनुमति मिल सकती है। परिषद अध्यक्ष अवधेश वर्मा का कहना है कि दो किलोवाट तक 200 यूनिट बिजली खर्च करने वाले संबंधित उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पूर्व में पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने आयोग को सुझाव दिया था, लेकिन उसे अब तक लागू नहीं किया गया है। गांव में लगभग 15 से 20 लाख ऐसे घरेलू बिजली उपभोक्ता हैं जिनके द्वारा आजीविका के लिए घर के ही एक हिस्से में किराना आदि की दुकान संचालित की जा रही है।

दहेज समेत 30 तरह के मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं करेगी पुलिस

लखनऊ। डीजीपी राजीव कृष्ण ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किया है कि जिन मामलों में कानून के तहत केवल परिवाद (शिकायत) का प्रविधान है, उनमें एफआईआर दर्ज करना पूरी तरह गलत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ द्वारा इस विषय पर आपत्ति जताए जाने के बाद डीजीपी ने यह निर्देश जारी किया है। उन्होंने निर्देश में स्पष्ट किया है कि कई बार पुलिस नियमों के विपरीत एफआईआर दर्ज कर लेती है। इससे आरोपित को न्यायालय में लाभ मिल जाता है। साथ ही पूरी जांच प्रक्रिया प्रभावित होती है। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद इसे गंभीर त्रुटि मानते हुए डीजीपी ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज करने से पहले यह अनिवार्य रूप से जांच लें कि संबंधित मामले में एफआईआर दर्ज करने का कानूनी प्रविधान है या नहीं।

रसोई गैस सिलेंडर के रिसाव से घर में लगी आग

इटौंजा (लखनऊ)। इटौंजा थाना के अंतर्गत अटेसुवा गांव में गुरुवार की सुबह एक किसान के घर में सुबह का खाना बन रहा था। तभी रसोई गैस सिलेंडर में रिसाव के चलते आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जिसकी वजह से घर में रखी हजारों की गृहस्थी व अनाज जलकर खाक हो गया। आग लगने से गांव में हड़कंप मच गया। अटेसुवा गांव के मेंड़ई ने बताया सुबह सब लोग खेत में काम करने जा रहे थे। घर पर खाना बन रहा था तभी रसोई गैस सिलेंडर में रिसाव हो गया। जिसकी वजह से आग लग गई।

लखनऊ एमपी-एमएलए कोर्ट का फैसला, मुख्तार से आमने-सामने चली थी गोलियां

माफिया बृजेश सिंह 2004 के कैंट फायरिंग केस में बरी

फैसला

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ । लखनऊ के बहुचर्चित 2004 कैंट फायरिंग मामले में बड़ा फैसला आया है। 22 साल बाद MP-MLA कोर्ट ने इस केस में आरोपी बृजेश सिंह को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। यह मामला उस समय सुर्खियों में आया था जब मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद राय के काफिले आमने-सामने आ गए थे और दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी।

मामले में मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय, बृजेश सिंह पर हत्या का प्रयास, बलवा आदि की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई थी।

मामले में श् एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। बृजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह, सुनील राय, आनंद राय, अजय सिंह उर्फ गुड्डू बरी किए गए। शनिवार को पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह एमपी एमएलए कोर्ट में मौजूद रहे। 13 जनवरी को 2004 में कैंट थाना क्षेत्र में सदर रेलवे क्रॉसिंग पर दोनों गुटों के बीच फायरिंग हुई थी। कृष्णानंद राय ने मुख्तार अंसारी और उसके साथियों पर एफआईआर दर्ज कराई थी।

दोनों ही उस समय विधायक थे और अपने-अपने समर्थकों के साथ यात्रा कर रहे थे, जिससे स्थिति अचानक तनावपूर्ण हो गई।

घटना वर्ष 2004 की है, जब लखनऊ के कैंट क्षेत्र में दो प्रभावशाली नेताओं के काफिले अचानक आमने-सामने आ गए थे। बताया जाता है कि उस समय मुख्तार अंसारी अपनी पत्नी के साथ गाजीपुर से लखनऊ आ रहे थे, जबकि कृष्णानंद राय लखनऊ से वापस गाजीपुर लौट रहे थे।

कुछ ही पलों में शुरू हो गई अंधाधुंध फायरिंग

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जैसे ही दोनों पक्ष आमने-सामने आए, पहचान होते ही माहौल गरमा गया और कुछ ही क्षणों में दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो गई। करीब पांच मिनट तक चली इस फायरिंग में कई राउंड गोलियां चलीं, जिससे इलाके में दहशत फैल गई थी।

हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना सामने नहीं आई थी, लेकिन घटना ने प्रदेश की राजनीति और कानून-व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए थे।

भाजपा जिला इकाइयों के गठन में नए चेहरों को लेकर भारी विरोध

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर भले ही जिला इकाईयों का पुनर्गठन कर रही है, लेकिन इसको लेकर वबाल भी तेज होता जा रहा है। लंबे समय बाद जिलों की टीमें बदलने के बाद से कुछ जिलों में नए चेहरों की छवि और अनुभव को लेकर विरोध के स्वर फूट पड़े हैं। कहीं कम अनुभवी चेहरों को महामंत्री जैसा अहम पद देने से उबाल है तो कहीं आपराधिक छवि के चेहरों को संगठन में स्थान मिलने से कार्यकताओं की नाराजगी बढ़ी है। विरोध में कई जिलों में पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं के इस्तीफे होने से पार्टी चिंतित है। नए सिरे से संगठन की समीक्षा करते हुए पार्टी डैमेज कंट्रोल की कसरत कर सकती है। भाजपा को 98 संगठनात्मक जिलों में पदाधिकारियों की टीमें बनानी है। ब्रज, पश्चिम, अवध, कानपुर और काशी क्षेत्र में अभी 17 जिलों की टीमों पर सहमति नहीं बन पाई है। बाकी जिलों की टीमें घोषित की जा चुकी है। अयोध्या महानगर में महामंत्री बनाए गए शिवेंद्र सिंह पर दर्जनों मुकदमे दर्ज होने का आरोप लगाते हुए पुराने कार्यकर्ता विरोध में उतर गए हैं।

यूपी के 1.50 लाख बच्चों की चमकेगी किस्मत

'स्कूल चलो अभियान' 1 अप्रैल से होगा शुरू

हेमन्त कृष्ण

तमसा संकेत, लखनऊ। प्रदेश में 1.50 लाख से अधिक ड्रापआउट बच्चों को फिर से स्कूल से जोड़ने के लिए 'स्कूल चलो अभियान' का आगाज एक अप्रैल से किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए इस अभियान को प्राथमिकता के आधार पर चलाने को कहा है। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा की ओर से जारी आदेश के अनुसार, शैक्षिक सत्र 2026-27 में अभियान दो चरणों में संचालित होगा। पहला चरण एक अप्रैल से 15 अप्रैल तक और दूसरा चरण एक जुलाई से 15 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से जोड़ने पर विशेष जोर रहेगा। यू-डायस आंकड़ों के मुताबिक परिषदीय विद्यालयों में करीब 1,50,660 बच्चे ड्रापआउट श्रेणी में चिन्हित हैं। इन बच्चों की पहचान और नामांकन के लिए शारदा ऐप में 'ड्राप आउट स्टेट्स' नाम से नया माड्यूल जोड़ा गया है। इसके जरिए शिक्षकों को ड्रापआउट बच्चों की सूची मिलेगी, जिनका नामांकन सुनिश्चित करना होगा। यदि कोई बच्चा पहले से ही विद्यालय में पढ़ रहा है, तो उसकी स्थिति एप पर अपडेट करनी होगी। वहीं, यदि छात्र किसी अन्य स्कूल में नामांकित है तो संबंधित विद्यालय का यू-डायस कोड दर्ज करना अनिवार्य होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अभियान के साथ इस प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए, ताकि सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में जोड़ा जा सके।

योगी सरकार 1 अप्रैल से शुरू करने जा रही स्पेशल अभियान

उत्तर प्रदेश में जनगणना की तैयारी हुई तेज

इसको जन अभियान बनाने का लक्ष्य

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जनगणना-2027 की तैयारी तेज हो गई है। इसके तहत होने वाले मकान सूचीकरण व मकान की गणना के लिए शनिवार को एक दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद कंचन वर्मा ने कहा कि जनगणना के आंकड़े देश के विकास की दिशा को तय करते हैं। जनगणना को जन-जन की भागीदारी से जोड़कर जन अभियान बनाया जाए, जिससे सही आंकड़े प्राप्त हो सकें। जनगणना कार्य में यदि कोई विसंगति पाई गई या कोई किसी कार्य को बाधित करेगा तो उसके विरुद्ध जनगणना अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। जनगणना कार्य निदेशालय में आयोजित कार्यक्रम में आयुक्त ने कहा कि प्रदेश में जनगणना 22 मई से 20 जून 2026 तक की जाएगी। यह पूरी तरह डिजिटल रूप में होगी। सभी डाटा संग्रहण, प्रविष्टि, सत्यापन एवं निगरानी कार्य डिजिटल प्लेटफार्म्स के माध्यम से किए जाएंगे। निदेशक जनगणना शीतल वर्मा ने जनगणना 2027 की प्रक्रिया, समय-सीमा एवं डिजिटल रूपांतरण के संबंध में प्रस्तुति दी, जिसमें राज्य की तैयारी और प्रस्तावित कार्ययोजना की जानकारी दी गई।

एक दिवसीय प्रशिक्षण में आयुक्त राजस्व परिषद ने अधिकारियों को दिए निर्देश

देश के विकास की दिशा को तय करते हैं जनगणना के आंकड़े

उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में ओलावृष्टि से 244.23 हेक्टेयर फसल की हुई क्षति

लखनऊ। प्रदेश में बीते कई दिनों तक खराब मौसम व ओलावृष्टि के 21 जिलों में कुल 244.23 हेक्टेयर फसल क्षतिग्रस्त हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल इसका संज्ञान लेकर सभी जिलाधिकारियों को अन्नदाताओं के नुकसान की भरपाई करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में आपदा से प्रभावित 286 किसानों को अब तक 13,34,217 रुपये की राहत राशि वितरित की जा चुकी है। वहीं, अतिवृष्टि (अधिक वर्षा) के चलते स्थिति अधिक गंभीर रही। इस दौरान कुल 14,207 किसान प्रभावित हुए, जिनमें से 9,992 किसानों को अब तक 4,47,24,779 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। इसके अलावा, बीते दिनों 15 से 25 मार्च तक हुई बेमौसम भारी वर्षा से सहारनपुर के पांच गांवों में 11 हेक्टेयर फसल क्षति दर्ज की गई, जिसमें 44 किसान प्रभावित हुए हैं। ललितपुर की तीन तहसीलों में 1650.75 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल क्षति दर्ज की गई है, जिसमें कुल 3142 किसान प्रभावित हुए हैं। सरकार सभी जिलों में फसल क्षति का आकलन करा रही है, जिससे पात्र किसानों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जा सके।

बजट की लूट, किसानों से धोखा और एमओयू के नाम पर गुमराह कर रही सरकार

'भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े का बना दिया रिकॉर्ड'

भाजपा सरकार पर अखिलेश यादव का हमला

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री Akhilesh Yadav ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े का नया रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता को झूठे सपने दिखाकर ठगा जा रहा है और बजट के पैसे का खुलेआम बंदरबांट हो रहा है।

"हर विभाग में कमीशनखोरी"

अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार के हर विभाग में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है। चाहे जल जीवन मिशन हो या लोक निर्माण विभाग, हर जगह कमीशनखोरी का खेल चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि डबल इंजन सरकार प्रदेश को लूटने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि अयोध्या, वाराणसी और नोएडा समेत कई क्षेत्रों में किसानों की जमीनें छीनी जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के

अखिलेश यादव ने प्रदेश के विकास को "शून्य" बताते हुए कहा कि सरकार फर्जी एमओयू के जरिए जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने मांग की कि यदि इन सभी एमओयू की जांच कराई जाए तो सरकार का सच सामने आ जाएगा।

किसानों की जमीन पर राजनीति का आरोप

सपा प्रमुख ने भाजपा को "भूमाफिया पार्टी" बताते हुए कहा कि किसानों की जमीनों का सही मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। सरकार जमीन अधिग्रहण कर अपने चहेते उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है।

खराब प्रबंधन के चलते प्रदेश के कई एयरपोर्ट ठप पड़े हैं। चित्रकूट और कुशीनगर एयरपोर्ट समेत घरेलू उड़ानों के लिए तैयार किए गए 6 एयरपोर्ट से उड़ानें बंद हैं।

अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार अरबों रुपये के निर्माण सिर्फ ठेके बांटने और कमाई के लिए कर रही है, न कि हवाई सेवाएं शुरू करने के लिए। अंत में उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार और लूट से परेशान है और आने वाले 2027 के चुनाव में उसे सत्ता से बाहर कर देगी।

पृष्ठ 01 का शेष...

पीएम मोदी ने सऊदी...

यह मीटिंग पहले तुर्किये में होनी थी, लेकिन बाद में इसे पाकिस्तान शिफ्ट कर दिया गया। रूस की न्यूक्लियर कामों से जुड़ी सरकारी कंपनी रोसएटम का कहना है कि ईरान के बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के आसपास हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कंपनी के मुताबिक वहां हो रहे हमले अब सीधे तौर पर परमाणु सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। इससे पहले अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने भी बुशहर के आसपास हमले की जानकारी दी थी। हालांकि रिएक्टर को कोई नुकसान नहीं हुआ और न ही किसी तरह का रेडिएशन फैला। यमन सरकार ने हूती लड़ाकों पर आरोप लगाया है कि वह देश को बेवजह के युद्धों में घसीट रहा है। यमन सरकार के मुताबिक, हूती लड़ाके ईरान के समर्थन में काम कर रहे हैं, उनका यह कदम देश की सुरक्षा के लिए खतरा है।

इससे पहले आज सुबह खबर आई थी कि हूती लड़ाकों ने इजराइल पर मिसाइल दागी थी, जिसे बीच में ही रोक दिया गया।

हूती लड़ाके यमन का एक हथियारबंद समूह है। ये देश की सरकार के खिलाफ लड़ रहा है और यमन के कई इलाकों पर इसका कब्जा है। इन्हें ईरान समर्थक माना जाता है।

ईरान से छपने वाले अंग्रेजी अखबार तेहरान टाइम्स ने अपने पहले पन्ने पर अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है। अखबार ने 'नरक में स्वागत है' (वेलकम टू हेल) लिखते हुए कहा है कि अगर अमेरिकी सैनिक ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए आए तो वे सिर्फ ताबूत में ही वापस जाएंगे। यह बयान उस समय आया है जब खबरें चल रही हैं कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में करीब 10,000 और सैनिक भेजने पर विचार कर रहा है।

ईरान की जंग में पहली...

इजरायली सेना के मुताबिक, मिसाइल लॉन्च के बाद दक्षिणी इजरायल के शहरों, खासकर बीयर शेबा के आसपास सायरन बजने लगे. यह इलाका इजरायल के अहम रणनीतिक ठिकानों के करीब माना जाता है. इससे पहले भी ईरान और लेबनान के हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे थे, लेकिन यमन से हमला इस जंग को एक नए मोर्चे पर ले जा सकता है.

दरअसल, हूती विद्रोही लंबे समय से ईरान के करीबी माने जाते हैं और 2014 से उन्होंने यमन की राजधानी सना पर नियंत्रण बना रखा है. 2015 में सऊदी अरब के नेतृत्व में गठबंधन ने इनके खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया था. हालांकि, हाल के वर्षों में सऊदी अरब और हूतियों के बीच एक अस्थायी युद्धविराम बना हुआ था, जिसके कारण अब तक वे इस बड़े संघर्ष से दूर थे. लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं. हूती पहले भी गाजा युद्ध के दौरान लाल सागर में शिपिंग मार्गों को निशाना बना चुके हैं. उनकी क्षमता लंबी दूरी तक हमला करने की है, जिससे न सिर्फ इजरायल बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर भी असर पड़ सकता है.

अयोध्या में मंत्री दया...।

शनिवार को आखिरी दिन यज्ञशाला में मंत्रोच्चारण के बीच 5 हजार से अधिक यजमानों ने आहुति दी। इसके बाद लोग घर चले गए, तभी हादसा हो गया। संयोग अच्छा था कि यज्ञ समाप्त हो चुका था और पूरा पंडाल खाली था। नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता। मुख्य अग्निशमन अधिकारी MP सिंह ने बताया आग लगने की सूचना पर तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गईं थीं। करीब 10 गाड़ियों ने 2 घंटे के प्रयास के बाद आग पर काबू पा लिया। किसी जनहानि की सूचना नहीं है।

असम में 90 से ज्यादा...

चंद्रशेखर ने पहले शिवनकुट्टी को बहस की चुनौती दी थी, जिसे मंत्री ने स्वीकार कर लिया था और 29 मार्च को पूजपुरा में बहस आयोजित करने का प्रस्ताव रखा था।

चेन्नई (तमिलनाडु) AIADMK महासचिव एडप्पाडी के. पलानीस्वामी ने उत्तरी चेन्नई क्षेत्र में रोड शो किया। रंगिया (असम) में शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सत्ता में बने रहने के लिए वोट बैंक बनाने के लिए घुसपैठ का मॉडल अपनाया। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाबेश कलिता के समर्थन में आयोजित चुनावी रैली में उन्होंने कहा कांग्रेस सत्ता में थी, तब असम का जल, जंगल और जमीन घुसपैठियों को सौंप दी गई। पुडुचेरी में 28 मार्च को घर पर वोटिंग के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने 102 साल की बुजुर्ग वोटर के के घर पहुंचे।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रविवार को असम विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणापत्र जारी करेंगे। गुवाहाटी में शनिवार को AICC महासचिव जितेंद्र सिंह ने बताया कि यह घोषणापत्र कई महीनों की मेहनत का नतीजा है, जिसके दौरान हमारे नेताओं और सदस्यों ने राज्य भर के लोगों से संपर्क साधा। तमिलनाडु के करूर से कांग्रेस सांसद एस जोतिमणि ने DMK के नेतृत्व वाले गठबंधन के तहत पार्टी की सीट चयन प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता के अभाव का आरोप लगाया है और दावा किया है कि पार्टी के हितों से पूरी तरह समझौता किया गया है।

राहुल ने सुधाकरन...

सुधाकरन, केरल के पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व राज्य कांग्रेस अध्यक्ष हैं। वे विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन पार्टी नेतृत्व ने मना कर दिया। इसक कारण वे पार्टी से नाराज थे।

जेवर एयरपोर्ट बन...

देशवासियों से कहूंगा कि धैर्य और एकजुटता के साथ इस संकट का सामना करें। ये पूरी दुनिया को परेशान करने वाला संकट है। प्रधानमंत्री ने कहा देश के राजनीतिक दलों से कहना चाहता हूं कि संकट की घड़ी में ऐसी बातें करने से बचें, जो देश के लिए नुकसानदायक हैं। देश को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। एयरपोर्ट के पहले फेज का काम पूरा हो गया है। इसमें करीब 3300 एकड़ जमीन पर टर्मिनल और रनवे बनाए गए हैं। यह टर्मिनल हर साल लगभग 1.2 करोड़ यात्रियों को संभाल सकेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 11 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।

सपा ने पश्चिमी यूपी को लूट का एटीएम बना दिया था। जब हमारी सरकार बनी तो यूपी में सपा की सरकार थी। शुरू के 2-3 सालों में उन्होंने जेवर एयरपोर्ट का काम नहीं होने दिया, लेकिन जैसे ही यहां भाजपा सरकार बनी तो जेवर एयरपोर्ट की नींव पड़ी, निर्माण हुआ और अब शुरू भी हो गया।

पीएम ने कहा कि हमारी सरकार विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर बड़ा निवेश कर रही है। हाईवे और एक्सप्रेसवे पर 17 हजार करोड़ से अधिक खर्च किया गया है। 2014 में रेलवे में सिर्फ 20 हजार किमी रूट का बिजलीकरण हुआ था। अब इसे 40 हजार किमी कर दिया गया है। ब्रॉडगेज से सभी क्षेत्र को जोड़ दिया गया है। कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक ट्रेन पहुंच चुकी है। देश में नदी जलमार्गों की संख्या भी बढ़ रही है।

विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी हर क्षेत्र में देश काम कर रहा है।

पीएम ने कहा कि यहां के किसानों का उत्पाद दुनिया के बाजारों में जा सकेगा। आपके गन्ने से इथेनॉल बनाया गया है। उससे कच्चे तेल पर देश की निर्भरता कम हुई है। इथेनॉल का उत्पादन न बढ़ता तो देश को हर वर्ष लगभग 700 करोड़ लीटर कच्चा तेल विदेशों से मंगवाना पड़ता। किसानों के परिश्रम ने देश को संकट के समय में इतनी बड़ी राहत दी है। इथेनॉल से देश के साथ किसानों को फायदा हुआ है। डेढ़ लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा बची है। देश के किसानों को ये पैसा मिला है।

उन्होंने कहा कि यहां के गन्ना किसानों ने तो पहले के दिन भी देखे हैं, जब कई सालों तक गन्ने का बकाया लटका रहता था। आज भाजपा की डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से गन्ना किसानों की स्थिति बेहतर हुई है।

पीएम मोदी विपक्ष के...

राजनीति के लिए गलत बयानबाजी करने के लिए राजनीतिक बहस में कुछ नंबर तो पा लेंगे, लेकिन देश को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों को देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी कुछ लोगों ने गुमराह किया, झूठ बोले, लेकिन जनता ने चुनावों के दौरान ऐसी राजनीति को नकार दिया। दुकरा दिया। मुझे भरोसा है कि देश के राजनीतिक दल इससे सबक सीखेंगे और एकजुट प्रयासों को बल देंगे, ताकत देंगे।

एयरपोर्ट 2040 तक...

कुर्सी जाने के डर से पहले के सत्ताधारी यहां आने से डरते थे। जब यहां सपा सरकार थी और मैंने नोएडा आने का कार्यक्रम बनाया। तब पुराने मुख्यमंत्री (अखिलेश) इतने डरे हुए थे कि वे कार्यक्रम में आए ही नहीं। मुझे भी डराने की कोशिश की गई, कहा गया- नोएडा मत जाइए। अभी-अभी प्रधानमंत्री बने हैं।

तमसा संकेत
tamsa.newslko@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक विद्या देवी द्वारा कृष्णा डाइनेस्टी प्रिंटिंग प्रेस म0 न0 195 सेक्टर 6-बी, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड लखनऊ-226 029 (उ0प्र0) से मुद्रित व प्रकाशित।

सम्पादक : विद्यादेवी

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा

समाचार पत्र में प्रकाशित लेख, राजनीतिक विश्लेषण, लेखकों के अपने विचार हैं। सम्पादक का इन विचारों से सहमत होना आवश्यक नहीं हैं।
मो0- 9415799533
R.N.I. NO. UPHIN/2021/83676